04 - विचार आधारित राजनीति से ही बदलेगी व्यवस्था

05 - कृत्रिम बौद्धिकता और न्याय-निर्णयन की निष्पक्षता

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 31 अगस्त , 2026

06 - आजकल की ईसी का आलम ही कुछ और है....

07 - मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में आवेदनों का त्वरित...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 328, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

जाति जनगणना को लेकर सियासी दल सच में गंभीर हैं?

इमरान क़ुरैशी

जाति की गिनती कैसे होगी? संख्याएँ कैसे गिनी जाएँ? और लोगों की पहचान कैसे की जाए? आम लोगों को यह कोई मुश्किल सवाल नहीं लगेगा। लेकिन जब पहचान जाति की हो, तो भारत जैसे देश में यह बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। करीब दो हफ़्ते पहले एक बड़े अख़बार के ओपिनियन पेज पर चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता प्रोफ़ेसर योगेंद्र यादव ने इसी मुद्दे पर कहा था कि था कि अगर लोगों से सिर्फ़ एक खुला सवाल पूछा जाए, 'आपकी जाति क्या है? ', तो नतीजे 2011 जैसे ही हो सकते हैं। 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना कराई गई थी। उसमें जातियों की संख्या 1931 की जनगणना में दर्ज 4,147 से बढ़कर 4 लाख 67 हज़ार तक पहुँच गई थी। 2011 में जुटाए गए आँकड़ों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। यह डेटा सार्वजनिक भी नहीं किया गया। जनगणना सिर्फ़ आबादी गिनने का काम नहीं है। यह सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए ज़रूरी आँकड़े भी उपलब्ध कराती है। 2027 की जनगणना फ़रवरी से शुरू होने वाली है. यह सात साल की देरी के बाद हो रही है। प्रोफ़ेसर योगेंद्र यादव ने अपने लेख में तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजातियों के नाम सरकार के पास पहले से मौजूद हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल ड्रॉप-डाउन मेन्यू में किया जा सकता है। इससे सामान्य वर्ग की गणना करना भी मुश्किल नहीं रहेगा।

इस बहस ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक दल अचानक ख़ामोश क्यों हो गए हैं। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरी कवायद का मक़सद समाज के वंचित तबकों के लिए विकास नीतियाँ तैयार करना बताया जाता है।

विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ा सवाल जाति से जुड़ा खुला प्रश्न है। जनगणना के लिए तैयार 40 सवालों में जाति का ज़िक्र सिर्फ़ एक बार किया गया है। यह सवाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति के रूप में शामिल है।

जनसंख्या विशेषज्ञ और जवाहरलाल नेहरू विवि के पूर्व प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम एम. कुलकर्णी ने कहा कि जाति पर खुला सवाल पूछने से बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग नाम सामने आते हैं। 2011 में भी यही हुआ था। इस काम के लिए व्यापक तैयारी की ज़रूरत होगी। समाजशास्त्रियों, मानवविज्ञानियों और सांख्यिकीविदों को मिलकर समान नामों की पहचान करनी होगी और उन्हें व्यवस्थित श्रेणियों में रखना होगा। उदाहरण के लिए 'गौडा' शब्द का मतलब अलग-अलग इलाक़ों में अलग हो सकता है। पूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण राज्यों के स्तर पर होना चाहिए।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़ के जेआरडी टाटा चेयर विज़िटिंग प्रोफ़ेसर नरेंद्र पाणी ने कहा, 'लोग अपनी जाति या उपजाति का नाम गणनाकर्मी को बताएँ। पहले लोगों के जवाबों को जस का तस दर्ज किया जाना चाहिए। बाद में ज़िला या तालुका स्तर के विशेषज्ञ स्थानीय नामों का मिलान कर सकते हैं। फिर इन नामों को मानकीकृत श्रेणियों में रखा जा सकता है। अलग-अलग नामों और वर्तनी को मिलाने के लिए बड़े डेटा सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। प्रोफ़ेसर पाणी का मानना है कि ड्रॉप-डाउन मेन्यू की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। असल सवाल यह है कि जाति का निर्धारण कौन करे। गणनाकर्मियों को उपजातियों की पहचान करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर मौके पर ही वर्गीकरण किया गया तो मूल जानकारी खोने का ख़तरा रहेगा। यह काम बाद में विशेषज्ञों को करना चाहिए।

हालाँकि, अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफ़ेसर अश्विनी देशपांडे की राय में ड्रॉप-डाउन मेन्यू में पहले से तैयार जातियों की सूची होनी चाहिए। हर राज्य के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी समुदायों की सूची है। अगर किसी जाति का नाम ड्रॉप-डाउन सूची में नहीं है, तो उसे अलग से लिखा जा सकता है। सूची में 'बताना नहीं चाहते' का विकल्प भी होना चाहिए। अगर पहले से तैयार ड्रॉप-डाउन सूची नहीं दी गई तो 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना जैसी स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है।

जनगणना संचालनालय के पूर्व उप महानिदेशक के. नारायणन उन्नी का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनगणना विभाग में जाति गणना का अनुभव और विशेषज्ञता कम हो गई है। कई दशकों से विभाग ने जाति गणना का काम नियमित तौर पर नहीं किया है। प्रवासन और समाज में आए बदलाव जैसी जटिल परिस्थितियाँ भी सही गणना और वर्गीकरण को मुश्किल बनाती हैं। उन्नी के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में गणनाकर्मी ड्रॉप-डाउन सूची का इस्तेमाल करने के बजाय लोगों द्वारा बताई गई जाति को लिख रहे हैं। इस मामले में मिश्रित मॉडल अपनाया जाना चाहिए। प्रमुख और व्यापक रूप से पहचानी जाने वाली जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन कोड उपलब्ध कराए जाएँ। इससे ग़लतियाँ कम होंगी और दफ़्तरों पर काम का बोझ भी घटेगा।

समाजशास्त्री सुरिंदर एस. जोधका का कहना है कि मौजूदा ढाँचा जाति की सार्थक गणना नहीं कर पाता। प्रोफ़ेसर जोधका का कहना है कि जाति भारतीय समाज की संरचना का एक अहम संकेतक है। फिर भी नौकरशाही में उदासीनता है और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी दिखाई देती है। '

द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह का कहना है कि सिर्फ़ सरकार में ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी झिझक दिखाई दे रही है। शुरुआत में कांग्रेस ने राजनीतिक मजबूरी में जाति जनगणना की मांग उठाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा लगे झटके ने राहुल गांधी का भरोसा और बढ़ाया कि जाति जनगणना राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद मुद्दा हो सकती है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी जाति जनगणना की बात सिर्फ़ औपचारिक तौर पर करते हैं। हालांकि, हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जाति जनगणना के मुद्दे पर खुला पत्र लिखा है। इस में उन्होंने केंद्र सरकार की जाति नगणना के मौजूदा फॉर्मेट को 'भ्रामक' बताया है और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। सिंह का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा के ऊँची जाति वाले वोट बैंक में भी कुछ संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। डीके सिंह का कहना है कि इसके बाद से पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, 'अब पार्टी के पास एक नया फ़ॉर्मूला है। उनके मुताबिक़, पार्टी 'पेंडोरा बॉक्स' खोलने से बचना चाहती है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को लगता है कि इससे ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं जिनका अनुमान लगाना मुश्किल होगा।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

जो चल रहा था वो चल रहा है।
कहाँ कहीं कुछ बदल रहा है।
करीब तुम हो इसीलिए वो
अभी से इतना उछल रहा है।
है चाँद पे हाथ जाने किसका,
जो आज सूरज निगल रहा है।
दिखा रहा है निज़ाम करतब
हमारा दिल भी बहल रहा है।
तनीं है मुट्ठी गरम है लहजा
सवाल कोई उबल रहा है।
है विषधरों की कमी वनों में
तो मोर दिल्ली टहल रहा है।
बुझा है अश्कों से घर का चूल्हा
धुँआ यहीं से निकल रहा है।
है तिफ़्ल दिल का 'अनिल' ये ज़िद्दी,
जो चाँद पाने मचल रहा है।

- **अनिल चौबे**

संकट की घड़ी में पूरी सरकार है बाढ़ पीड़ितों के साथ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

- मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया पैदल भ्रमण, किया नुकसान का मुआयना
- अधिकारियों को 3 दिन तक चित्रकूट में ही रहकर राहत पहुंचाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने आश्रय स्थल जाकर बाढ़ प्रभावितों को दिए वस्त्र, घरेलू सामग्री और खाद्यान्न

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को रीवा से सीधे चित्रकूट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में बाढ़ की आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का मुआयना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राचीन मुखार विन्द के पास बनाए गए आश्रय स्थल (राहत शिविर) पहुंचकर सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनके कुशल-क्षेम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में हमारी पूरी सरकार आप लोगों के साथ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदाकिनी नदी की बाढ़ से नदी का पानी घरो में घुसने से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा चित्रकूट की अधोसंरचनाओं को भी क्षति पहुंची है। उन्होंने सभी प्रभावितों से कहा कि सरकार और प्रशासन आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ है। सभी प्रभावितों को उनके हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चित्रकूट में जन जीवन सामान्य होने तक सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यहीं रूककर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आश्रय स्थल पर बांदा के बबेरू से आए श्रद्धालु श्री राजू सिंह से बात की। श्री राजू ने बताया कि वे 20 लोगों के साथ कामतानाथ स्वामी के दर्शन करने आए थे। बाढ़ का पानी होने से वे सब अपने घर वापस नहीं लौट पाए। उन्होंने बताया कि इस आश्रय स्थल पर प्रशासन द्वारा उन सभी के लिए भोजन, पानी, नाश्ते की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आश्रय स्थल पर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को वस्त्र, घरेलू सामग्री और खाद्यान्न आदि राहत सहायता सामग्री भी वितरित की।

जल भराव वाले क्षेत्रों का किया पैदल भ्रमण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चित्रकूट नगर के रामधाम मोहल्ले में जलभराव (बाढ़) से प्रभावित क्षेत्रों का पैदल भ्रमण किया। उन्होंने कीचड़ से सने मार्ग में पैदल चलकर प्रभावितों के घरों तक पहुंचकर जल भराव से हुए नुकसान का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री रामफल गर्ग और श्री किस्मत कुमार गर्ग के घर पहुंचकर जलभराव से हुए नुकसान की जानकारी ली तथा प्रभावित परिवारों से आत्मीय चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सतना से चित्रकूट मार्ग पर सियाराम कुटीर स्थित माधव धर्मशाला के समीप अग्रहरि किराना स्टोर पहुंचकर दुकानदार श्री कामता प्रसाद गुप्ता से मुलाकात की और उनकी दुकान में पानी भरने से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ है और सभी प्रभावितों को नियमानुसार हरसंभव राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ओरछा में 14 साल बाद बीजेपी का महामंथन

- मिशन 2028 को लेकर सीएम मोहन और शिवराज ने खींचा ब्लूप्रिंट, सिंधिया भी मौजूद

निवाड़ी (नप्र)। इंदौर में उमंग सिंघार का सरकार पर हमला मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज करते हुए भगवान श्रीराम की नगरी ओरछा में 14 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का भव्य शुभारंभ हो गया है। ऐतिहासिक होटल राजमहल में आयोजित इस उच्चस्तरीय महामंथन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत राज्यभर के करीब 350 दिग्गज प्रतिनिधि जुटे हैं। बैठक की शुरुआत रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के सामूहिक श्रवण और ध्वजारोहण के साथ की गई।

- मिशन 2028-29 का बन रहा रोडमैप- इस दो दिवसीय महामंथन का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को धरातल पर और अधिक मजबूत करना है। बैठक में हर बूथ, सबसे मजबूत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कार्यसमिति के प्रत्येक सदस्य को एक-एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जा रहा है।

उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान,यूरेनियम पर डील

ताशकंद (एजेंसी)। पीएम मोदी ने रविवार को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की है। इस दौरान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राज्य पुरस्कार ओली दाराजली डस्टलिक से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज हम तीन सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट समझौतों को औपचारिक रूप दे रहे हैं। आपके देश में न्यू ताशकंद जैसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी विकसित की है। इन विकास कार्यों में अपनाई गई बेहतरीन प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को समझने के लिए उज्बेक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए हमें खुशी होगी। पीएम मोदी ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक लंबी अवधि की व्यवस्था भी करेंगे।

मोदी ने की उज्बेकिस्तान की तारीफ

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने आपकी किताब देखी। इसमें आपने हमारे आपसी आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और आगे बढ़ने के लिए एक समय-सीमा तय की है। मैं इस पहल की सराहना करता हूं। मुझे भरोसा है कि साथ मिलकर काम करने से हम इस दिशा में तेजी से प्रगति करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कल रात डिनर के दौरान हमारी सार्थक बातचीत हुई।

भारत के डीएनए में ही है एकता और विविधता

- भागवत ने कहा-हम अलग होकर भी एक-दूसरे से जुड़े हैं
- कहा-गलत सोच इंसान को जानवरों के करीब ले जाती है

न्यूयार्क (एजेंसी)। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शनिवार रात करीब 42 मिनट स्पीच दी। उन्होंने कहा कि एकता और विविधता भारत के डीएनए में है। लोग अलग दिखते हैं, उनके रहने के तरीके हैं, लेकिन सभी के बीच एक जन्मजात जुड़ाव है। भागवत ने कहा- विविधता में एकता भारत की पारंपरिक सोच है और देश समय-समय पर पूरी दुनिया को इसका एहसास कराता रहा है। उन्होंने आगे कहा- सोचने की क्षमता इंसान के लिए एक वरदान है। सही सोच इंसान को भगवान के करीब ले जाती है, जबकि गलत सोच उसे जानवरों के करीब ले जाती है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा भारतीय मूल के अमेरिकी शामिल हुए। इसका आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग ने किया। कार्यक्रम में 30 देशों के 180 धार्मिक नेता पहुंचे थे।

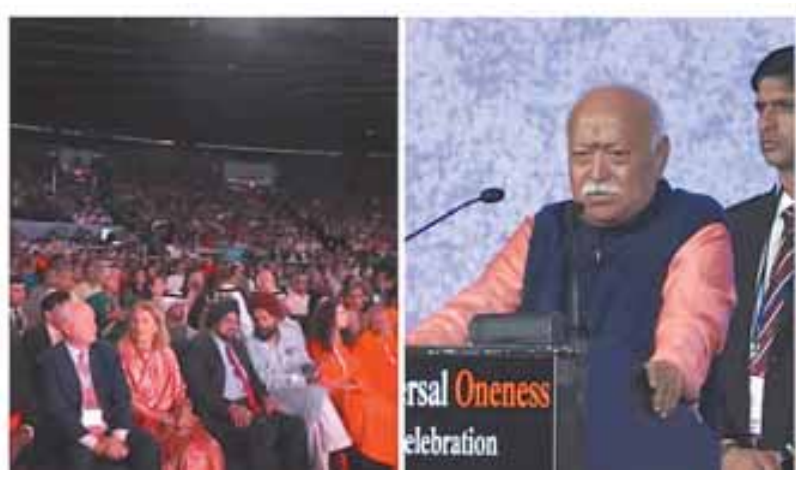

धर्म सिर्फ पूजा नहीं जीवन को संतुलित रखने का नियम

भागवत ने कहा कि भारत में जिस सिद्धांत को धर्म कहा जाता है, उसे सिर्फ धर्म या पूजा के तौर पर नहीं समझना चाहिए। धर्म वह व्यवस्था है जो ब्रह्मांड और जीवन को संभालती है। यह जीवन की अलग-अलग स्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

भागवत ने कहा कि पैसा, सामान और दूसरी भौतिक सुविधाएं हमेशा खुशी नहीं दे सकतीं। भौतिक सुख अस्थायी होता है और बहुत ज्यादा सुविधाएं होने के बावजूद संतुष्टि की कमी रह सकती है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से भागवत ने कहा कि आपकी पहली जिम्मेदारी अपनी कर्मभूमि के प्रति है उसके प्रति वफादार रहना चाहिए।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 31 अगस्त 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सवाल पूछने या असहमति जताने पर छात्रों को सजा देना असंवैधानिक

● जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कह दी बड़ी बात,दीक्षांत समारोह में की टिप्पणी ● कहा-असहमति रखने पर छात्रों को धमकाया या दंडित नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि केवल इसलिए छात्रों को धमकाया या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कि उन्होंने पद पर बैठे अधिकारियों या अथॉरिटी के लोगों से अलग विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक नागरिकता का मूल तत्व है। दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एलएलएम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार अवज्ञा का कृत्य नहीं है। यह नागरिकता, स्वतंत्रता और संवैधानिक जिम्मेदारी की अनिवार्य अभिव्यक्ति है।

जस्टिस भुइयां ने कहा सवाल पूछने पर छात्रों को नहीं धमका सकते और इसके लिए उन्हें सजा

देना संविधान के खिलाफ है। विश्वविद्यालयों में मुक्त विचार और कठिन सवालों की जगह होनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि छात्रों को अलग राय रखने पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह सत्ता और पद का दुरुपयोग भी है।

लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक ही तरह सोचें

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग एक ही तरह सोचें। संविधान अलग-अलग विश्वास, विचार और मान्यताओं वाले लोगों को समान गरिमा के साथ रहने और लोकतांत्रिक जीवन में भाग लेने का ढांचा देता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज इस आधार पर नहीं बनाया जा सकता कि हर व्यक्ति एक जैसा सोचे। मतभेद स्वाभाविक हैं और उन्हें व्यापक संवैधानिक ढांचे के भीतर स्वीकार करना जरूरी है। उनके मुताबिक, असहमति के लिए जगह के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का वास्तविक अर्थ ही समाप्त हो जाएगा।

असहिष्णुता भी हिंसा का एक रूप...भारत बुद्ध और गांधी की भूमि है

जस्टिस भुइयां ने असहिष्णुता को संविधान की भावना के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि असहिष्णु मानसिकता संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती और यह एक अन्य प्रकार की हिंसा बन सकती है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध और गांधी की भूमि है। भारतीय समाज में हिंसा और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संविधान बोलने, सोचने और अलग विश्वास रखने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब असहमति को वैध मतभेद के बजाय दबाने, खारिज करने या दंडित करने योग्य चीज समझा जाने लगे, तब असहिष्णुता संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती है।

यूपी की चर्चित आईएएस दिव्या मित्तल का इस्तीफा

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी की चर्चित आईएएस दिव्या मित्तल (43) ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अभी वह लखनऊ में राजस्व विभाग में विशेष सचिव हैं। दिव्या ने मुख्य सचिव

एसपी गोयल को इस्तीफा भेज दिया। रविवार सुबह उन्होंने फेसबुक-इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। दिव्या मित्तल का अचानक इस्तीफा ब्यूरोक्रेसी में सुर्खियों में है। इस्तीफा क्यों दिया, यह स्पष्ट नहीं है। चर्चा है कि 4 महीने से वह साइडलाइन थीं। फील्ड पोस्टिंग चाहती थीं। 2013 बैच की दिव्या 13 साल से नौकरी कर रही थीं। अभी उनकी 17 साल की नौकरी बची थी। बेंगलुरु से एमबीए की डिग्री लेने के बाद लंदन में नौकरी की।

संक्षिप्त समाचार

मेसी इवेंट के टिकट खरीदने वाले फैंस का पैसा होगा रिफंड

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के शासनकाल में हुए वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर लियोनी मेसी के कार्यक्रम के टिकट खरीदने वाले फैंस का

वापस करने का ऐलान किया है। 2025 में कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी का इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें अव्यवस्था के लिए सरकार के लिए काफी आलोचना हुई थी। इस अव्यवस्था के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार के खेल मंत्री अरूप बिस्वास को जिम्मेदार बताया गया था। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के खेल बजट से टिकट का पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही 33 हजार फैंस को पैसा रिफंड हो जाएगा। विशेष नेशनल स्पोर्ट्स डे इवेंट में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लियोनी मेसी के बहुत सारे फैंस हैं।

गंभीर मामलों में न्यायपालिका संसद का इंतजार नहीं करती

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए तरह के फ्रॉड पर संसद के कानून बनाने का इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से कार्रवाई करती है। उन्होंने शनिवार को लंदन में 43वें इंटरनेशनल सिम्पोजियम

ऑन इकोनॉमिक क्राइम के समापन समारोह में यह बात कही। सीजेआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम पर स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें ठग वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस अधिकारी,न्यायिक अधिकारी या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से इस समस्या के स्तर का आंकलन करने को कहा है।

आधी रात हिरासत में लिए गए आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। आईएएस अफसर ज्ञानेंद्र कुमार गंगवर को हिरासत में ले लिया गया है। सीआईडी ने वेटनरी ऑफीसर (पशु चिकित्सा

अधिकारी) के लिए कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आईएएस अफसर को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार से सीआईडी ने लगातार 9 घंटे की कड़ी पूछताछ की थी। उनसे यह पूछताछ शुक्रवार से शुरू हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन शनिवार को भी अधिकारियों से पूछताछ की और रविवार को उन्हें हिरासत में लिया गया। ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को सीआईडी ने नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था।

मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले ही हुआ बप्पा का आगमन

● खेरानी चा राजा पांडाल की धूम, भक्तिमय हो गया है शहर ● लालबागचा राजा सहित कई प्रसिद्ध पंडालों में उमड़ेगी भीड़

मुंबई (एजेंसी)। गणेश चतुर्थी.. इस त्योहार की तैयारी महीनों पहले ही शुरू हो जाती है और गणपति बप्पा के स्वागत का इंतजार करते हुए शहर का जोश और उत्साह एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। हर बार की तरह इस बार भी खेरानी चा राजा 2026 के शानदार आगमन के साथ मुंबई भक्ति के रंग में रंग गई है। धूम-धाम से हो रहे जश्न से लेकर गणपति

बप्पा मोरया के जयकारों तक पूरा शहर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है और भक्त बप्पा का स्वागत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। भगवान गणेश की भव्य और सुंदर मूर्ति का स्वागत करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती दिखी। मुंबई के लोग इस त्योहार का पूरे साल इंतजार करते हैं और माहौल में जो उत्साह होता है वह वाकई बेमिसाल होता है।

भक्ति के उत्सव में बदल देता है त्योहार

10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार मुंबई को रंगों, संगीत और भक्ति के उत्सव में बदल देता है। इन दिनों में लोग बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए अलग-अलग पंडालों में जाते हैं। यह उत्सव इतना भव्य होता है कि भक्त अपने प्रिय बप्पा की एक झलक पाने के लिए घंटों और कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय तक इंतजार करते हैं। शहर के कुछ सबसे मशहूर पांडालों में लालबागचा राजा,जीएसबी सेवा मंडल और मुंबईचा राजा से लेकर चिंचपोकलीचा चिंतामणि,खेतवाड़ी गणराज तक शामिल हैं।

हॉर्न बजाने पर कार का कांच फोड़ा, चाकू मारा और ले ली जान... सभी हत्यारे गिरफ्तार

पुलिस की लाठियां पड़ते ही मांगने लगे माफी

उज्जैन (नप्र)। मध्यप्रदेश के उज्जैन में ट्रैक्टर शोरूम संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेष तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करने से पहले घटना स्थल पर लेकर पहुंची, जहां कथित तौर पर आरोपियों की हेकड़ी सामने आने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपियों को लाठियां पड़ती नजर आईं और वे माफी मांगते दिखाई दिए। कार्रवाई देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

तीन दिन पहले मामूली विवाद में हुई थी हत्या- मामला उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के दमदमा इलाके का है। करीब तीन दिन पहले गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे 27 वर्षीय यश मित्तल अपने दोस्तों को कार से उनके फ्लैट पर छोड़ने जा रहे थे। यश मूल रूप से तराना के रहने वाले थे और आगर रोड मंडी में ट्रैक्टर शोरूम का संचालन करते थे। वह परिवार के साथ ऋषिनगर एक्सटेंशन में रहते थे।

पुलिस के मुताबिक, यश अपने दोस्तों अभय व्यास, मंगल सहित अन्य लोगों को छोड़ने जा रहे थे।

हॉर्न बजाने पर भड़के युवक

आरोप है कि हॉर्न बजाने की बात को लेकर युवकों ने यश और उनके दोस्तों से विवाद शुरू कर दिया। गाली-गलौज के बाद युवकों ने कार के कांच फोड़ दिए और उसमें बैठे लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान यश को पकड़कर उसके पेट में चाकू मार दिया गया। घटना से घबराए उनके दोस्त किसी तरह वहां से निकलकर मदद मांगने माधवनगर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका दोस्त मौके पर फंस गया है और उसकी जान को खतरा है।

पुलिस पहुंची, लेकिन मौके पर नहीं मिला यश- दोस्तों की सूचना पर पुलिस उनके साथ घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से भाग चुके थे। यश भी मौके पर नहीं मिला। पुलिसकर्मियों और उसके दोस्तों ने करीब तीन घंटे तक उसकी तलाश की।

सुबह करीब 5 बजे जिला पंचायत के बाहर एक फोटोकॉपी की दुकान के पीछे यश लहूलुहान और अचेत अवस्था में मिला। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद माधवनगर थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर सात आरोपियों को चिन्हित किया। पुलिस ने एक दिन पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इंदौर में उमंग सिंघार का सरकार पर हमला

छात्र हनुमान की तरह होते हैं, लंका में आग लगाएं तो जलना तय

इंदौर (नप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रविवार को इंदौर पहुंचे। यहां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सांवेर विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रीना बोरसी सेतिया की ओर से आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सिंघार ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों, शहर के जल संकट, सरकारी जमीनों पर कब्जे, युवाओं को रोजगार, ओबीसी आरक्षण और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल किए।

भागीरथपुरा रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग- भागीरथपुरा पानी कांड को लेकर उमंग सिंघार ने सरकार से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भागीरथपुरा का मामला नहीं है बल्कि पूरे इंदौर से जुड़ा हुआ विषय है। लोगों को किस तरह का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है यह गंभीर सवाल है और इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए।

सिंघार ने कहा कि मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है लेकिन यह भी साफ होना चाहिए कि क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी तय हुई है या नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अधिकारी दोषी हैं तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब इंदौर की जनता को भी जांच रिपोर्ट सामने लाने की मांग करनी चाहिए। सिंघार ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी।

भू-माफिया को लेकर भी सरकार पर हमला- इंदौर में सरकारी जमीनों पर कब्जे और भू-माफिया के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। सिंघार ने आरोप लगाया कि इंदौर से लेकर उज्जैन तक भू-माफिया सक्रिय हैं और उन्हें भाजपा नेताओं का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलों में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए ।

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे 898 कर्मचारी

नेपाल में संकट, छह इंच छेद कर पाइप से पहुंचाई हवा

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल में बाढ़ के बाद हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। करीब 898 कर्मचारी अब भी फंसे हैं, जबकि 361

कर्मचारियों को अब तक बचाया जा चुका है। त्रिशूली-3 'ए' हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ कामयाबी मिली है। बचावकर्मी मशीनों की मदद से मिट्टी और गाद हटा रहे हैं। सुरंग में 6 इंच का छेद कर पाइप के जरिए हवा पहुंचाई जा रही है। अब इसे बड़ा कर मैनहोल बनाने की तैयारी है, ताकि बचाव दल सुरंग के अंदर जाकर लोगों की तलाश कर सके। 26 अगस्त को नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी।

पोर्न वेबसाइट्स पर सीक्रेट चैटिंग कर रहे आतंकी

पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इसी पर मैसेज भेजते हैं

एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पहचान छिपाने की कोशिश

श्रीनगर (एजेंसी)। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सीक्रेट चैटिंग के लिए अब पोर्न वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसका सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। आतंकी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर में भर्ती किए गए लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। ताकि पारंपरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी से बचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इन पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म पर रियल-टाइम चैट टूल मौजूद होते हैं। जो आसपास डेट (पार्टनर) ढूंढ़ने में मदद करने के नाम पर काम करते हैं। लेकिन हैंडलर्स इनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधि के लिए कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई खास डिजिटल टूल्स की जांच शुरू की है। आतंकी हैंडलर कोटेक्स और कोनियन जैसे टोर आधारित मैसेजिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

अब बारिश बन गई आफत,नहीं मिल रही राहत

एमपी के चित्रकूट में होटलों में फंसे लोग,हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू

छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना का दीघा घाट डूब चुका है। वहीं, बगहा के डुमरिया घाट पर गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 15 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के सतना, चित्रकूट, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बाढ़ जैसे हालात हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से करीब 26 फीट ऊंची बह रही है। घाट किनारे करीब 400 दुकानें डूब चुकी हैं। लोग घरों और होटलों में फंसे हैं। 2 हेलीकॉप्टर के साथ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। राजस्थान में जयपुर समेत 15 शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इस साल मानसून के कमजोर रहने के कारण जयपुर सहित 17 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के

अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण -मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण और मानसून ट्रफ लाइन के प्रभाव से रीवा संभाग में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटीय और निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहे हैं। देश में मानसून के जोरदार प्रहार के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से ताजा और बेहद गंभीर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 26 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है।

तीन प्रमुख सड़कें होंगी अतिक्रमण मुक्त

इंदौर। शहर में लगातार बनी रहने वाली यातायात जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्ती की तैयारी कर ली है। जुलूस, जलसे और त्योहारों के दौरान बिगड़ने वाले यातायात को देखते हुए हुई उच्चस्तरीय बैठक में तीन प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में हुए निर्णय का असर रविवार सुबह से ही नजर आया। निगम की गाड़ी ने तीनों मार्गों पर अनाउंसमेंट कर दुकानदारों और वाहन चालकों को अतिक्रमण व गलत पार्किंग हटाने की चेतावनी दी। पहले चरण में राजमोहल्ला चौराहा से जवाहर मार्ग होते हुए राजवाड़ा, कृष्णपुरा पुल-मृगनयनी से रीगल तिराहा और शास्त्री मार्केट-नसिया क्षेत्र से रिवर साइड रोड होते हुए कृष्णपुरा तक का मार्ग शामिल किया गया है। निगम ने लोगों से कहा कि सड़क पर रखा सामान और अस्थायी अतिक्रमण खुद हटा लें। लंबे समय से या गलत तरीके से खड़े वाहनों को भी हटाने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल बड़ा गणपति से कृष्णपुरा मार्ग को अभियान में शामिल नहीं किया गया है। अगले चरण में सुभाष मार्ग और सपना-संगीता मार्ग को भी जोड़े जाने की संभावना है।

ड्रग के साथ नाइजीरियन गिरफ्तार

इंदौर। नाइजीरिया मूल की एक महिला को चंदन नगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला मुंबई से बस के जरिए इंदौर आई थी और यहां मादक पदार्थ की डिलीवरी देने वाली थी। पुलिस ने पहले से मिली सूचना के आधार पर उस पर नजर रखी और शनिवार को चंदन नगर इलाके में घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से 57 ग्राम से ज्यादा एमडी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल की टीम को सूचना मिली थी कि मुंबई से जोया नाम की नाइजीरियन महिला इंदौर आकर कोकीन और अन्य मादक पदार्थों की डिलीवरी करती है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने महिला की गतिविधियों और इंदौर आने-जाने की जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस को जानकारी मिली कि राखी के अगले दिन जोया मुंबई से इंदौर आ सकती है। इसके बाद टीम ने मुंबई से इंदौर आने वाली बसों पर नजर रखना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक शनिवार को जोया इंदौर पहुंची। बस से उतरने के बाद पुलिस टीम ने उस पर नजर रखी और चंदन नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 57 ग्राम से अधिक एमडी बरामद हुई।

5 रूट पर दौड़ेंगी 26 ई-बसें

इंदौर। पांच प्रमुख मार्गों पर करीब 26 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। इससे भोपाल, उज्जैन, मांडव, खरगोन, खंडवा और सेंधवा तक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने इसके लिए योजना तैयार की है। बसों का संचालन निजी संचालकों को सौंपा जाएगा। योजना के अनुसार भोपाल के लिए 8, उज्जैन के लिए 6, मांडव के लिए 2, खरगोन-खंडवा के लिए 8 और सेंधवा के लिए 2 बसें प्रस्तावित हैं। संचालक केवल बस चलाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि करीब आठ साल तक इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। सरकार की योजना धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर परिवहन से जोड़ने की है। इसी कड़ी में उज्जैन के साथ मांडव को भी ई-बस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। बसों का संचालन निर्धारित मार्गों पर अनुबंध मॉडल के तहत करने की तैयारी है।

आधी रात दबिश, 4 वारंटी गिरफ्तार

इंदौर। देपालपुर पुलिस ने आधी रात चलाए गए सघन कांबिंग गश्त अभियान में लंबे समय से फरार चल रहे चार स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खड़ी निवासी शिवनारायण नकुम, बरोदा पंथ निवासी बापूसिंह, देपालपुर निवासी गोवर्धन प्रजापत और खड़ी निवासी लालचंद्र को दबोचा। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक बघेल के साथ राजेंद्र सुमन, अमित सिंह राजपूत और दीपेंद्र गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चोइथराम मंडी में दिनदहाड़े लूट

इंदौर। चोइथराम सब्जी मंडी में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े होटल कर्मचारी को घेरकर नकदी और कीमती सामान लूट लिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना मंडी के गेट नंबर 2 और 3 के बीच हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। जानकारी के मुताबिक होटल कर्मचारी मुकेश रोजाना की तरह होटल के लिए सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचा था। खरीदारी करने के बाद वह बाहर की ओर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे रास्ते में घेर लिया।
आरोपियों ने कर्मचारी को डराया- धमकाया और जान से मारने की धमकी देकर उसकी जेब में रखी नकदी व कीमती सामान छीन लिया। इसके बाद बदमाश तेजी से मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने वारदात से पहले कर्मचारी की रेकी की थी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। दिनदहाड़े हुई लूट से मंडी में हड़कंप मच गया। व्यापारियों और खरीदारों में भी दहशत का माहौल है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

सड़क हादसों ने छीनी दो जिंदगी

इंदौर। शहर के अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुए हादसे में शिवपुरी निवासी 55 वर्षीय संजय की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं कनाड़िया बायपास पर कल दोपहर करीब 12 बजे अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सीरिया की महिला डॉक्टर ने फेसबुक पर दोस्ती कर 6.11 लाख रु ठग लिए

इंदौर। सोशल मीडिया पर विदेश की महिला से दोस्ती करना इंदौर के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को महंगा पड़ गया। सीरिया की डॉक्टर बनकर एक महिला ने उनसे संपर्क किया और बातचीत के दौरान भारत आने की बात कही। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा मेडिकल उपकरण और अन्य सामान रोक लिए जाने की कहानी सुनाकर रुपए मांगे गए। महिला के साथियों ने खुद को कस्टम और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी बताकर रिटायर्ड प्रिंसिपल को भरोसे में लिया और अलग-अलग खातों में कुल 6 लाख 11 हजार रुपए जमा करा लिए। मामले में आजाद नगर पुलिस ने शनिवार को शाहिन नगर निवासी डॉ अयाज कुरैशी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब जिन बैंक खातों में रकम पहुंची और जिन मोबाइल नंबरों से बातचीत हुई, इसकी जानकारी जुटा रही है।
फेसबुक पर हुई दोस्ती- आजाद नगर टीआई लोकेश भदौरिया के मुताबिक, डॉ अयाज कुरैशी की 1 मई 2026 को फेसबुक के जरिए सीरिया की रहने वाली आयशा खान नाम की महिला से दोस्ती हुई थी। महिला ने खुद को डॉक्टर बताया। फेसबुक पर बातचीत शुरू होने के बाद दोनों के बीच लगातार संपर्क बना रहा। कुछ समय बाद आयशा ने कुरैशी को बताया कि सीरिया में युद्ध के हालात हैं और वह वहां से भारत आकर रहने की तैयारी कर रही है। बातचीत के दौरान उसने भरोसा कायम किया और फिर कुछ दिनों बाद बताया कि वह दिल्ली पहुंच चुकी है।

भागीरथपुरा में 36 में से 24 मौत दूषित पानी से, दो अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी

पाइपलाइन बदलने और टेंडर में देरी को हादसे की बड़ी वजह माना

इंदौर। भागीरथपुरा के दूषित पानी कांड की जांच कर रही हाईकोर्ट की एक सदस्यीय न्यायिक समिति की रिपोर्ट में प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई है। रिपोर्ट के प्रमुख अंशों के अनुसार, घटना में 36 लोगों की मौत के मामलों की जांच में 24 मौतों को दूषित पानी से संबंधित माना गया है, जबकि 12 मामलों में मौत की वजह को स्पष्ट नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में पाइपलाइन बदलने में हुई देरी और टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने को दूषित पानी की समस्या का अहम कारण माना गया है। रिपोर्ट में 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, जांच समिति की पूरी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए इसमें दर्ज निष्कर्षों पर अंतिम स्थिति हाईकोर्ट की सुनवाई और आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में दूषित पानी से हुई मौतों के मामलों में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए तक मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। फिलहाल ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। समिति ने इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने की जरूरत बताई है। इसके अलावा दूषित पानी से प्रभावित और घटना में बीमार या घायल हुए लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई है। यदि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है तो भागीरथपुरा कांड के प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि में बड़ा बदलाव हो सकता है।

पाइपलाइन और टेंडर में देरी पर सवाल

जांच में भागीरथपुरा में दूषित पानी की समस्या के पीछे पाइपलाइन से जुड़े काम में हुई देरी को महत्वपूर्ण कारण माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि पाइपलाइन समय रहते बदल दी जाती तो दूषित पानी की स्थिति पैदा होने से रोकी जा सकती थी। समिति ने पाइपलाइन बदलने के काम में हुई देरी के साथ ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी पड़ताल की है। इस दौरान नगर निगम के जल विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, समिति ने यह देखने की कोशिश की कि पाइप लाइन बदलने का काम समय पर क्यों नहीं हो पाया और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस संबंध में क्या कदम उठाए।

एमआईसी को राहत मिली - रिपोर्ट से सामने आई जानकारी अहम पहलू यह भी है कि भागीरथपुरा कांड के लिए किसी जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल को भी इस मामले में क्लीन चिट दिए जाने की जानकारी है। इससे संकेत मिलता है कि समिति ने घटना की जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर तय की है। हालांकि, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को लेकर रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट रितेश इनानी के मुताबिक, उन्होंने जांच रिपोर्ट के कुछ अंश देखे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट काफी विस्तृत है और उसका पूरा अध्ययन अभी नहीं हो पाया है। प्रारंभिक तौर पर इसमें कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित- हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कर दी है। फिलहाल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और इसे रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखा गया है। संबंधित पक्षों के अधिवक्ता रजिस्ट्रार के पास जाकर रिपोर्ट का अध्ययन कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसकी प्रति सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराने की मांग भी अदालत के सामने रखी गई है। जब तक रिपोर्ट की आधिकारिक प्रति सार्वजनिक नहीं होती, तब तक सामने आए निष्कर्षों को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।
दिसंबर 2025 में आया था संकट- भागीरथपुरा में दिसंबर 2025 में दूषित पानी की समस्या सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग उल्टी-दस्त और दूसरी बीमारियों की चपेट में आ गए थे। देखते ही देखते मामला गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल गया था। 36 लोगों की मौत के बाद इस घटना को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति पर गंभीर सवाल उठे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद अदालत ने प्रभावित क्षेत्र में साफ पेयजल उपलब्ध कराने, बीमार लोगों के उपचार और प्रशासनिक इंतजामों को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक जांच समिति गठित की गई थी।
मामला 36 मौतों का नहीं - याचिकाकर्ता प्रमोद द्विवेदी की ओर से एडवोकेट मनीष यादव ने भी रिपोर्ट को लेकर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि भागीरथपुरा की घटना को केवल 36 मौतों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि शहर की पेयजल व्यवस्था में ऐसी खामी दोबारा न हो और जिम्मेदारी तय करने की ठोस व्यवस्था बने।

कांग्रेस छात्रों में पहुंच बढ़ाएगी, 12 सितंबर को इंदौर में राहुल गांधी को लाने की तैयारी

अंतिम तारीख और स्थल पर फैसला बाकी ; जीतू पटवारी के निवास पर बैठक

इंदौर। प्रदेश कांग्रेस अब छात्रों और युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में पार्टी की ओर से इंदौर में बड़े स्तर पर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम 12 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में रखा गया है। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की बात सामने आई है। राहुल गांधी के दौरे के साथ ही कार्यक्रम की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। आयोजन को लेकर प्रदेश कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, छात्रों की भागीदारी और आयोजन से जुड़े दूसरे पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में केबी बायजु, सत्यनारायण पटेल, शोभा ओझा, विपिन वानखेड़े, चिंटू चौकसे, सदाशिव यादव, संजय कामले, रीना बोरासी सहित कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
इंदौर को इसलिए चुना - 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए प्रदेश में इंदौर और जबलपुर के नाम पर विचार किया गया था। बाद में इंदौर को आयोजन के लिए चुना गया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, इंदौर प्रदेश का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। यहां बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से विद्यार्थी पढ़ाई के लिए शहर में आते हैं। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी हो सकती है। बैठक में आयोजन स्थल और कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों को आयोजन की तैयारियों से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपे जाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

छात्रों के मुद्दे राजनीतिक मुद्दा

कांग्रेस इस आयोजन के जरिए छात्रों से जुड़े सवालों को सामने लाने की तैयारी में है। पार्टी की कोशिश है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के बीच संवाद बनाया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस अपने राजनीतिक विचार और संदेश को युवाओं तक पहुंचाने का भी प्रयास करेगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम को लेकर शुरुआती चर्चा हो चुकी है। अब इंदौर में हो रही बैठकों और तैयारियों के बाद कार्यक्रम का स्वरूप सामने आने की उम्मीद है।

इंडिगो का विमान खराब, इंदौर से रीवा-जबलपुर की तीन उड़ानें रद्द

राखी पर घर जाने वालों को परेशानी, एयरपोर्ट पर हंगामा

इंदौर। देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानतल पर इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण खड़ा हो गया। इसके चलते रीवा और जबलपुर के बीच आने-जाने वाली 3 उड़ानें निरस्त करनी पड़ीं। उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशान हो गए। सबसे अधिक दिक्कत रीवा जाने वाले यात्रियों को हुई, क्योंकि उनके लिए दूसरी कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं थी। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा करते हुए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था करने की मांग की। जानकारी के अनुसार इंडिगो की उड़ान 10.50 बजे जबलपुर से रवाना होकर इंदौर पहुंचती है और यहां से 11.20 बजे रीवा के लिए उड़ान भरती है। यही विमान रीवा से दोपहर 3.20 बजे इंदौर लौटकर 3.40 बजे जबलपुर के लिए रवाना होता है। गुरुवार सुबह विमान तय समय पर जबलपुर से इंदौर पहुंच गया था। इसके बाद जब इसे रीवा के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही थी, तभी विमान में तकनीकी खराबी सामने आ गई।
समय पर नहीं हो सका सुधार- विमान में खराबी सामने आने के बाद एयरलाइंस के इंजीनियरिंग दल ने जांच शुरू की और उसे ठीक करने का प्रयास किया। काफी कोशिश के बावजूद तत्काल खराबी दूर नहीं हो सकी। इसके बाद कंपनी ने इंदौर से रीवा जाने वाली और रीवा से इंदौर आने वाली दोनों उड़ानों को निरस्त करने की सूचना दी। दोपहर तक विमान के ठीक नहीं होने पर इंदौर से जबलपुर जाने वाली उड़ान भी रद्द कर दी गई। इस तरह एक ही विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण रीवा और जबलपुर से जुड़ी कुल 3 उड़ानें प्रभावित हुईं।
कंपनी ने जताई असमर्थता- उड़ानें रद्द होने की सूचना मिलने के बाद यात्रियों में नाराजगी फैल गई। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा करते हुए कंपनी से दूसरे विमान की व्यवस्था करने की मांग की। यात्रियों का कहना था कि त्योहार के मौके पर उन्हें समय पर अपने घर पहुंचना था, लेकिन उड़ान रद्द होने से उनकी पूरी यात्रा व्यवस्था बिगड़ गई।कंपनी ने तत्काल दूसरे विमान की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई। यात्रियों को टिकट का पैसा वापस लेने या दूसरी उड़ान में पुनः बुकिंग कराने का विकल्प दिया गया। अधिकांश यात्रियों को अगले दिन की उड़ानों में बुकिंग दी गई। रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी संख्या में यात्री अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे थे। ऐसे समय में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को न केवल अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े, बल्कि उनकी यात्रा भी एक दिन आगे खिसक गई।

पंढरीनाथ के टीआई के हाथों में 15 सौ राखियां, खाकी की नई पहचान

टीआई सतीश पटेल की सामुदायिक पुलिसिंग का अंदाज

इंदौर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आमतौर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर उनसे सुरक्षा का वचन मांगती हैं। मगर शहर में एक ऐसा पुलिस अफसर भी है, जिसकी कलाई पर हर साल एकाध नहीं, बल्कि हजार से डेढ़ हजार महिलाएं और युवतियां राखी बांधने पहुंचती हैं। शहर के कई थानों की कमान संभाल चुके सतीश पटेल को पूरे इलाके की जनता अफसर नहीं, अपने परिवार के सदस्य और भाई के रूप में देखती है। खाकी और जनता के बीच के इस अनोखे जुड़ाव को उन्होंने 'पुलिस हमारी मित्र, टीआई हमारा भाई' अभियान का नाम दिया है। इस आत्मीय रिश्ते का बीज वर्ष 2016 में बोया गया था। उस समय सतीश पटेल सिवनी जिले के छपारा थाने में पदस्थ थे। त्योहार के दिन ड्यूटी की बाध्यता के कारण उन्हें अपने घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकी। उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सतीश पटेल के काम करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। आसपास के करीब 150 गांवों की महिलाएं अचानक थाने पहुंचने लगीं। वे अपने क्षेत्र के थानेदार को राखी बांधने आई थीं। अचानक उमड़ी भीड़ को देखकर सतीश पटेल खुद गाड़ी लेकर ग्रामीण इलाकों में निकल पड़े, ताकि बहनों को थाने तक आने का कष्ट न उठाना पड़े।
फर्ज भी निभाते हैं अफसर- समय के साथ लोगों में यह विश्वास पक्का होता गया कि यह पुलिस अफसर सिर्फ अपराध रोकने वाला नुमाइंदा नहीं है, बल्कि मुसीबत के वक्त संगे भाई की तरह साथ खड़ा रहने वाला मददगार भी है। वर्ष 2016 के बाद से हर रक्षाबंधन पर यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अलग-अलग शहरों में अपनी पदस्थापना के दौरान वे अब तक 20,000 से अधिक राखियां बंधवा चुके हैं।
महिलाओं का भरोसा बना ताकत- थानेदार के साथ इस पारिवारिक जुड़ाव का सीधा लाभ पुलिस की व्यवस्था को मिला। महिलाओं को यह भरोसा हो गया कि वे बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं सीधे अपने भाई तक पहुंचा सकती हैं। इसके चलते महिला अपराधों और इलाके की अन्य गतिविधियों की सटीक सूचनाएं सीधे पुलिस मुख्यालय तक पहुंचने लगीं। कई बार तो जागरूक महिलाओं ने असामाजिक तत्वों को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस तरह राखी के एक धागे ने जन-पुलिसिंग (कम्युनिटी पुलिसिंग) की मजबूत नींव रख दी।

अस्पताल में महिला अधिकारी से दुष्कर्म की घटना, आरोपी फरार

सहकर्मी स्वास्थ्य अधिकारी पर केस दर्ज, धमकी भी दी

कमरे में अंदर से बंद किया

महिला के मुताबिक, ऊपर पहुंचने के बाद सोहेल उसे एक कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने महिला का मुंह दबाया और उसे जमीन पर पटक दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि सोहेल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया। चाकू दिखाकर उसे डराया और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह आरोपी की धमकी से इतनी डर गई थी कि उसका विरोध नहीं कर सकी। घटना के दौरान आरोपी लगातार उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा। वारदात के बाद सोहेल कमरे से निकलकर वहां से चला गया।

इंदौर। जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 28 वर्षीय महिला अधिकारी ने अपने सहकर्मी स्वास्थ्य अधिकारी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने कमरे में बंद करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर गर्दन पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो पहले उसे और फिर उसके परिवार को मार डालेगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोहेल आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ है। पीड़िता भी इसी स्वास्थ्य केंद्र में उसके साथ काम करती है। महिला ने पुलिस को बताया कि सोहेल पिछले कुछ दिनों से उस पर जबरदस्ती करने का दबाव बना रहा था। वह लगातार उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। धमकियों के कारण महिला डरी हुई थी और उसने पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। 29 अगस्त की सुबह महिला रोज की तरह स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। इसी दौरान सोहेल ने उसे ऊपर की मंजिल पर चलकर वहां का निरीक्षण करने के लिए कहा। महिला ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। आरोप है कि इस पर सोहेल ने कहा कि वह उसके साथ कई साल से काम कर रही है, इसके बावजूद उस पर भरोसा नहीं करती। उसने महिला को वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी भी दी। इस बात से घबराकर महिला उसके साथ ऊपर की मंजिल पर चली गई।

परिजन के साथ पहुंची थाने

घटना के बाद महिला ने अपने परिजन को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार रात सोहेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। घटनास्थल की पड़ताल के साथ मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। आरोपी घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

संपादकीय

नेपाल त्रासदी और चीन

नेपाल में ग्लेशियर टूटने से मची भयंकर तबाही, नए आसन्न संकट और राहत कार्यों के बीच देश के उत्तरी पड़ोसी चीन की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने नेपाल को समय रहते आपदा की चेतावनी नहीं दी। अगर दी होती तो कम से कम जान का नुकसान तो कम किया जा सकता था। हालांकि चीन ने ऐसे किसी भी आरोप को खारिज किया है। हालांकि बाद में उसने कुछ सूचनाएं पहले ही साझा की हैं। लेकिन इस मामले में भी चीनी कार्यशैली और पारदर्शिता फिर सवालों के घेरे में है। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ में 724 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।2400 अभी भी लापता हैं, जिनमें 589 विदेशी नागरिक हैं और इनमें भी 49 भारतीय हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नेपाली सेना और भारतीय बचाव दल मिलकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दो अन्य झीलों के फटने की चेतावनी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इन सबके बीच चीन की नीयत और उसके चेतावनी तंत्र को लेकर आलोचना की जा रही है। बताया जा रहा है कि चीन अभी भी सच्चाई पर पर्दा डालने में लगा है। जिसमें स्थानीय लोगों के बनाए कुछ दृश्य कथित तौर पर ऑनलाइन मंचों से गायब करने और विदेशी पत्रकारों को प्रभावित क्षेत्रों और वहां के लोगों तक पहुंच बनाने में बाधा डालना शामिल है। बाढ़ और विनाश से सम्बंधित खबरें और वीडियो भी सेंसर किए जा रहे हैं। वैसे भी चीन में चीन में लोग बाढ़ की जानकारी के लिए मुख्य रूप से सरकारी मीडिया पर निर्भर रहना हैं। सरकारी रिपोर्टों में राहत और बचाव कार्यों को प्रमुखता दी गई है, जबकि बाढ़ से हुए नुकसान के स्तर की सीमित जानकारी ही सामने आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत की ग्यिरोंग काउंटी में एक सीमा चौकी को मिट्टी के मलबे के साथ बहने वाली वीडियो चीनी सोशल मीडिया से हटा दिया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्यिरोंग में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उधर विदेशी पत्रकारों पर पाबंदी से नेपाल के बाहर बाढ़ से हुए नुकसान का स्वतंत्र आकलन मुश्किल हो गया है। लंदन स्थित स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के चीन संस्थान के निदेशक स्टीव त्सांग के अनुसार चीन में किसी भी रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले बहुत उच्च स्तर से मंजूरी जरूरी होती है। वहां तिब्बत से जुड़ी हर चीज को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है। नेपाल के पूर्व सांसद राजेंद्र बजगाई ने भी पारदर्शिता की कमी को लेकर चीन की आलोचना की है। उधर नेपाल में चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन वायरल ख़बरों का खंडन करते हुए कहा कि नेपाल के ग्यिरोंग सीमा क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ से चीन बेहद दुखी है और वह नेपाल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगा। भविष्य में हम मौसम, जल विज्ञान और भूगर्भीय जोखिमों से जुड़ी सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान, ख़ासकर सीमा पार होने वाली आपदाओं के मामले समन्वय मज़बूत करेंगे। ताकि सीमा के दोनों ओर लोगों की जान और संपत्ति की बेहतर सुरक्षा हो सके। दरअसल चीन के इस संदेहास्पद रवैये ने हर मामले में उसकी विश्वसनीयता को और कम किया है। उनकी नीयत और मंशा पर तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अपारदर्शिता और चालाकी चीन की स्थायी नीति रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी देश चीन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकता और न ही करना चाहिए।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

विचार आधारित राजनीति से ही बदलेगी व्यवस्था

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से एक बात मात्र अवश्य सकारात्मक हुई है कि अब भविष्य में भी अगर किसी गंभीर घटना पर दस-बीस हजार लोग इकट्ठे होंगे तो सरकारें उनके साथ समझौते करेंगी। तात्पर्य यह कि, भारत सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि कम संख्या होने पर वह जायज बात भी नहीं मानेगी और कुछ हजार लोग इकट्ठे होने पर वह जायज नाजायज जरूरी या गैर जरूरी सभी बातें मानेगी। वैसे तो 2023 में भी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के लंबे धरने के समय भी ऐसी ही घटना हुई थी और लगभग 1 वर्ष के निरंतर धरने के बाद वही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो किसानों के आंदोलन को गलत मानते थे, उनके आंख, मुंह, कान किसानों की आवाज के प्रति बंद थे, चुनाव पूर्व रातों-रात किसान समर्थक गये और तीनों बिल वापिस किये।

जंतर-मंतर के छात्र आंदोलन और 20 जुलाई के संसद मार्च ने कई प्रश्न और शंकाएं पैदा की हैं। इस आंदोलन के प्रति आशंकाओं के बारे में पहले लिख चुका हूँ। जो संशय मैंने व्यक्त किये थे उनमें से अधिकांश सच भी हुए हैं। अन्ना हजारे के वर्ष 2010 के अभियान के समय कारपोरेट के इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया ने जनमत को गुमराह किया था जिसकी असलियत अब सामने आ चुकी है। इस छात्र आंदोलन के पीछे के जो निहित उद्देश्य हैं वह भी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि जो घोषित लक्ष्य था वह इस अर्थ में सफल माना जाना चाहिये कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। जहां तक पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून का प्रश्न है, वह कानून तो 2024 में भी पारित हुआ था जिसमें पेपर लीक करने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान था। अब 2026 के नये कानून में जुर्माना की राशि बढ़ाकर 4 करोड़ तक और सजा की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष तक की गई है। प्रश्न जुर्माने या सजा अवधि का बढ़ाने का नहीं था, बल्कि उस कानून का क्रियान्वयन कैसा हुआ व कितना हुआ यह महत्वपूर्ण था? इन 2 वर्ष की अवधि में किसी भी पेपर लीक के अपराधी के खिलाफ कोई सजा या 1 करोड़ जुर्माने की सूचना मीडिया में नहीं आई।

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से एक बात मात्र अवश्य सकारात्मक हुई है कि अब भविष्य में भी अगर किसी गंभीर घटना पर दस-बीस हजार लोग इकट्ठे होंगे तो सरकारें उनके साथ समझौते करेंगी। तात्पर्य यह कि, भारत सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि कम संख्या होने पर वह जायज बात भी नहीं मानेगी और कुछ हजार लोग इकट्ठे होने पर वह जायज नाजायज जरूरी या गैर जरूरी सभी बातें मानेगी। वैसे तो 2023 में भी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के लंबे धरने के समय भी ऐसी ही घटना हुई थी और लगभग 1 वर्ष के निरंतर धरने के बाद वही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो किसानों के आंदोलन को गलत मानते थे, उनके आंख, मुंह, कान किसानों की आवाज के प्रति बंद थे, चुनाव पूर्व रातोंरात किसान समर्थक गये और तीनों बिल वापिस किये। मैंने तब भी इन 3 बिलों में से एक बिल को उचित माना था। और आज न केवल मैं, बल्कि अधिकांश किसान संगठन उसे उचित मान रहे हैं परंतु प्रचार मीडिया और भीड़ कई बार सत्य की आवाजों को दबा देती है। पेपर लीक मामले को लेकर मैंने 2024 में भी श्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। अभी मई 2026 में भी नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की थी परंतु प्रधानमंत्री और सरकार केवल ताकत और गाली की भाषा को समझती है। अगर मई माह में ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की बात को सुना होता तो जिस अपमान के साथ सरकार को झुकना पड़ा शायद यह वह नहीं होता।

इसके दो परिणाम संभावित है। पहला, यह कि आमजन में यह भावना पहुंची है और मजबूत होगी कि सरकारें तभी संवेदनशील होती है। जब लाचार होती है। हो सकता है कि भविष्य में सरकारें जन आंदोलन से शीघ्र बातचीत शुरू करे और उनकी समस्यायें हल करें, जैसा कि 25 जुलाई के बाद मप्र के भोपाल में किसानों के भोपाल मार्च के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों के द्वारा 21 बेरीकेड पार करने के बाद उनसे समझौता कर लिया। दूसरा यह भी संभावित है कि अब भीड़ की संख्यात्मक बल के आधार पर अनुचित मांगों को मानने को भी सरकारें लाचार होगी, हालांकि भीड़ का कानून सदैव सही नहीं होता। शाहबानो वाले प्रकरण में मुस्लिम भाईयों की भीड़ के सामने स्वर्गीय राजीव गांधी झुके और उसका परिणाम देश व उनकी पार्टी देख चुकी है। परंतु अब इस नई पीढ़ी को रिझाने समझाने, संवाद करने और गुमराह करने के लिये देश के कई राजनैतिक दल और विशेषतः प्रधानमंत्री और उनकी मातृ संस्था संघ सक्रिय हुई है जिन प्रधानमंत्री ने 21 बच्चों की पेपर लीक से उत्पन्न हुई निराशा के बाद आत्महत्या करने पर भी एक शब्द नहीं कहा, वही वह आजकल इंस्ट्राग्राम पर नियमित संवाद कर रहे हैं। जो संघ एक चाल के सिद्धांत पर पिछले सौ वर्षों से चल रहा था वह अब जनतंत्र, संवाद और मिलजुलकर निर्णय की बात करने लगा है।

इस छात्र आंदोलन में 14, 15 जुलाई तक मात्र कुछ सैकड़ा लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पर थे और इनमें न केवल कॉकरोच जनता पार्टी वाले बल्कि वामपंथी संगठनों एसएफआई, माले, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छात्र कांग्रेस व कुछ भीम आर्मी के नौजवान भी शामिल थे। परंतु इंस्ट्राग्राम, रील, मीम जैसे सोशल मीडिया के नये टूल्स ने एक ऐसा जुनून का गुब्बारा भीतर-भीतर भरा जिसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी, यहां तक कि सरकार को भी नहीं थी, उसके चलते 20 जुलाई को हजारों नौजवान व लोग जंतर-मंतर व दिल्ली की सड़कों पर उतरे। इतना ही नहीं 20 को संसद मार्च व लाठी चार्ज के बाद सारे देश में सरकार के प्रीति एक आक्रोश पैदा हुआ। स्वमेव छात्र, उनके अभिभावक अपने-अपने शहरों में सड़कों पर निकलना शुरू हुये। अब छात्र जो हाई स्कूल, कालेज या विवि में पढ़ते हैं उनका सबसे नजदीकी व प्रिय परिवार नहीं है बल्कि हाथ का मोबाइल है जिसे वे दिन रात व कभी-कभी तो सोते समय कान में लीड लगाकर साथ रखते हैं। यह तकनीक ने एक नया संवाद का माध्यम पैदा किया है जो बाहर नजर नहीं आता पर अंदर समुद्र के नीचे लहरों के समान चलता है और जब यह फैलना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी और उनके संघ परिवार के लोग जिन छात्रों को राष्ट्रद्रोही व विदेशी ताकतें, सनातन के विरोधी आदि-आदि रूप में देखते थे वे ही रात 12 बजे उनके प्रिय युवा मित्र हो गये इसके बाद प्रधानमंत्री, संघ और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी भाषा बदली है। दरअसल इस वाणी परिवर्तन के पीछे बड़ी भूमिका उन गंदी गालियों की है जिन्हें कुछ युवक-युवतियों ने न केवल उच्चारित की, बल्कि उन्हें बाकायदा सोशल मीडिया पर रील व मीम बनाकर पोस्ट किया। जब यह गलियां इंस्टाग्राम पर करोड़ नौजवानों और लोगों ने सुनी तो वे भी उत्साहित हुये। भीड़ तो किसान आंदोलन में भी थी पर उसकी आवाज सरकार ने 1 साल बाद चुनाव के पूर्व ही सुनी। परंतु इस बार चुनाव के ढाई वर्ष पहले और एक सप्ताह के अंदर यह आवाज इसलिए सुनी क्योंकि इस नई पीढ़ी की जमात ने उनका मान मर्दन कर दिया। न केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गालियां सुनने के बाद अपना स्वर बदला और रातों रात वे लोकतांत्रिक हो गए। संघ ने भी जिसके सह कार्यवाहक श्री होसबोले ने अपने बयान में छात्रों के पीछे सनातन व राष्ट्र विरोधी शक्तियों के होने का संकेत दिया था जिसकी पुष्टि डॉ.मोहन भागवत ने भी की थी, इन गालियों के बाद उनका सुर बदला और उन्हीं मोहन भागवत ने जब दिल्ली में अपनी संस्था के नाम गालियां सुनीं तो उन्हें लोकतंत्र और संवाद याद आ गया। उन्होंने पलटी मारकर बयान दिया कि नई पीढ़ी आदेश नहीं मानती इससे संवाद करें। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी जिन्होंने इन छात्रों को कॉकरोच कहकर संबोधित किया था उनकी याचिका सुनने इंकार कर दिया था। रातों-रात उनकी भाषा और सुर बदल गए, क्योंकि इस भीड़ ने उनके लिए भी गालियों से संबोधित किया, जैसे प्रधानमंत्री जी को किया था। वरना कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश पर एक सनातनी वकील ने जूता फेंका, उसके बाद श्री प्रबल प्रसाद सिंह एडवोकेट ने इन्हीं सूर्यकांत जी (मुख्य न्यायाधीश) का नाम लेकर कोर्ट रूम में गंदी गालियां दी तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय को युवकों के भाव समझ नहीं आये। अब जब सार्वजनिक रूप से करोड़ों लोगों ने उनको गालियां देना शुरू किया तो अचानक सर्वोच्च न्यायालय का हृदय परिवर्तन हो गया।

मैं गालियों का समर्थन नहीं करता, परंतु यह जो नई संस्कृति जन आंदोलन में गाली व उसके बाद सत्ता की उदारता का जन्म हो रहा है यह अपराध छात्रों का कम प्रधानमंत्री, संघ और सर्वोच्च न्यायालय का अधिक है। अब डॉक्टर मोहन भागवत भी छात्रों के नाम संवाद कर रहे हैं, हालांकि उनके संवाद में छात्र कितने थे यह पता नहीं, पर वह युवा पीढ़ी की भरपूर तारीफ कर रहे हैं। अगर अयोध्या की चंदा चोरी कांड ने अयोध्या में श्रद्धालुओं और चंदा की मात्रा कम कर दी तथा फिर ऐसे ही देश के अनेक मंदिरों में जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, सिद्धि विनायक मंदिर तक चंदा चोरी की बात सामने आने लगी, तो इनमें भी चढ़ावा, श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। उसी प्रकार जंतर-मंतर के धरना के बाद युवकों, छात्रों में जो घृणा और आक्रोश पैदा हुआ है, संघ की शाखाओं में युवकों की भागीदारी जो पहले अज्ञानता या एक कृत्रिम प्रभाव में हो रही थी उनके प्रति छात्र सावधान हुए हैं और उनकी संख्या घटी है। इसलिए उनको लुभाने के लिये संघ संवाद कर रहा है। हमारे क्षेत्र में यह कहावत है (देर आए दुरुस्त आए) (जब जागे तभी सवेरा) और (लातों के भूत बातों से नहीं मानते) अब इनमें से किस कहावत ने प्रधानमंत्री जी व संघ परिवार को प्रेरणा दी है मैं नहीं जानता, पर इस घटनाक्रम ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि प्रचार की नई-नई तकनीक के माध्यम से ही आमजन को आंदोलित किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि अब सरकार भी इस दिशा में सक्रिय होगी और नए-नए प्रयोग व प्रतिबंधों को अपनाएगी, पर कुछ समय तक तो यह टूल्स सरकार के खिलाफ और प्रभावी रहें काम आएंगे।

इस आंदोलन के एक धड़े के मुखिया श्री अभिजीत किसी राजनीतिक लक्ष्य या शक्तियों से प्रेरित हैं, यह संकेत मिलने लगे हैं। झारखंड में पेपर लीक हुआ वहां भी छात्र गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। सरकार के पानी की बोछारों पर वह जल नृत्य कर रहे थे। पर जंतर मंतर के आंदोलन करने वाले छात्र नेता झारखंड पर चुप हैं। इसी प्रकार पंजाब में नकल के विरोध करने वालों पर, लाठी चार्ज पर भी श्री अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दोनों मौन है। जो नीट के पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर आंसुओं से सराबोर मूर्ति श्री सोनम वांगचुक शायद आराम के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, कुछ नौजवान न्यूयॉर्क व बर्लिन पहुंच जाएंगे, पर प्रश्न यह है कि मीडिया जनित आंदोलन चाहे वह जंतर मंतर पर हो या रामलीला मैदान पर हो या रांची की सड़कों पर हो या चंडीगढ़ की सड़कों पर हो, छिपे तौर पर कुछ संपन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की राजनीति होती है जिसका शिकार देश और सिद्धांत की राजनीति होती है। एक फौरी मुद्दा हलचल पैदा कर सकता है, सरकार बदल सकता है पर व्यवस्था नहीं बदल सकता। व्यवस्था बदलने को तो विचार आधारित राजनीति ही बदल सकती है जिसे पीछे धकेलने को ये बुलबुले कारपोरेट पूंजीवाद पैदा करता है।

क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्ति

- डॉ. नरेश गौतम

सहायक प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर

समुदाय विमुक्त हुए लेकिन क्या खत्म हुआ कलंक?

आजादी के बाद भारत ने उस औपनिवेशिक कानून को समाप्त किया। 1952 में इन समुदायों को डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियों के रूप में पहचान मिली। लेकिन क्या कानून ख़त्म करने से उनके प्रति बनी मानसिकता भी समाप्त हुई, जो दशकों तक इन समुदायों को अपराध से जोड़ती रही। नाम बदला, कानून बदला, लेकिन सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन की गति बहुत धीमी रही। यही कारण है कि 31 अगस्त को केवल 'विमुक्ति दिवस' के रूप में मनाना पर्याप्त नहीं है। यह दिन आत्ममंथन का दिन भी होना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि जिन लोगों को राज्य ने कभी 'जन्मजात अपराधी' कहा था, क्या आज वही राज्य उन्हें पूर्ण नागरिक के रूप में समान अवसर दे पा रहा है?

31 अगस्त घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त समुदायों के लिए केवल यह कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है बल्कि यह उस इतिहास की याद है, जिसमें तमाम समुदाय को उसके जन्म और जीवन-जीने के तरीके के आधार पर अपराधी मान लिया गया था। 31 अगस्त 1952 को औपनिवेशिक शासन के कुख्यात क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त किए जाने के बाद इन समुदायों को कानूनी रूप से 'विमुक्त' किया गया। लेकिन सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक असहज सवाल हमारे सामने खड़ा है क्या कानून से मुक्ति सामाजिक जीवन में भी मुक्ति में बदल पाई है? ब्रिटिश शासन ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था। इस कानून ने अनेक समुदायों को जन्मजात अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया। यानी व्यक्ति ने कोई अपराध किया या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि महत्वपूर्ण यह था कि वह किस समुदाय में पैदा हुआ है। यह कानून केवल कानूनी नियंत्रण का माध्यम नहीं था, बल्कि इसने एक गहरा सामाजिक कलंक पैदा किया था।

आजादी के बाद भारत ने उस औपनिवेशिक कानून को समाप्त किया। 1952 में इन समुदायों को डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियों के रूप में पहचान मिली। लेकिन क्या कानून ख़त्म करने से उनके प्रति बनी मानसिकता भी समाप्त हुई, जो दशकों तक इन समुदायों को अपराध से जोड़ती रही। नाम बदला, कानून बदला, लेकिन सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन की गति बहुत धीमी रही। यही कारण है कि 31 अगस्त को केवल 'विमुक्ति दिवस' के रूप में मनाना पर्याप्त नहीं है। यह दिन आत्ममंथन का दिन भी होना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि जिन लोगों को राज्य ने कभी 'जन्मजात अपराधी' कहा था, क्या आज वही राज्य उन्हें पूर्ण नागरिक के रूप में समान अवसर दे पा रहा है? क्या उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? क्या उनके परिवारों के पास सुरक्षित आवास है? क्या उनके पास पहचान और निवास से जुड़े आवश्यक दस्तावेज हैं? क्या आज उनकी आजीविका सुरक्षित है? यह प्रश्न गहरे जरूर हैं लेकिन जरूरी हैं क्योंकि आज भी इन समुदायों की संख्या को लेकर भी देश के पास पूरी तरह स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रिया के आधार पर देश में 1,262 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान की गई है। सरकारी आँकड़ों में 425 विमुक्त और 810 घुमंतू समुदाय दर्ज हैं। विभिन्न आयोगों और अध्ययनों में इन समुदायों की आबादी कई करोड़ बताई गई है। रेणके आयोग के अनुमान के आधार पर यह संख्या लगभग 10 से 12 करोड़ तक बताई गई है। लेकिन वर्तमान जनगणना से प्राप्त कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय आंकड़ा उपलब्ध न होना स्वयं एक गंभीर नीतिगत समस्या है। जिस समुदाय की आज तक सही संख्या ही स्पष्ट न हो, उसके लिए योजनाएं कितनी प्रभावी हैं, इसका आकलन कैसे होगा? कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने परिवारों के पास दस्तावेज नहीं हैं, कितने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं और कितने परिवार आवासविहीन हैं इन सवालों के ठोस राष्ट्रीय आंकड़े हमारे पास क्यों नहीं हैं? आंकड़ों की यह कमी केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं है बल्कि यह इन समुदायों की अदृश्यता का प्रमाण भी है।

स्थायी पता होना कल्याणकारी राज्य की लगभग हर सुविधा की पहली शर्त बन माना जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन ही गतिशील है, उससे स्थायी पते की अपेक्षा करना कई बार व्यवस्था और समुदाय के बीच एक असंगत संबंध पैदा करता है। राशन कार्ड, स्कूल प्रवेश, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक पहुँच, हर जगह दस्तावेज और स्थायी निवास की आवश्यकता घुमंतू समुदायों के लिए एक बड़ी बाधा बनता रहा है। सबसे अधिक असर इनके बच्चों पर पड़ता है। एक घुमंतू परिवार जब आज एक स्थान पर और कुछ महीनों बाद दूसरे स्थान पर होता है, तो बच्चों की शिक्षा कैसे लगातार संभव हो सकती है? स्कूल की व्यवस्था स्थायी है, जबकि परिवार का जीवन गतिशील है।

उसका परिणाम यह होता है कि बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं या उनकी शिक्षा बार-बार छूटती रहती है। बाल श्रम, असुरक्षित रोजगार और कम उम्र में पारंपरिक काम में शामिल होना इसी समस्या को और गहरा करता है। घुमंतू महिलाओं की स्थिति तो और भी जटिल है। घुमंतू और विमुक्त समुदायों की महिलाओं को गरीबी, असंगठित श्रम, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता और सामाजिक असुरक्षा जैसी कई परतों वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनके विकास की कोई भी नीति केवल 'परिवार' को इकाई मानकर नहीं बनाई जा सकती बल्कि महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर अलग रणनीति आवश्यक है।

इसके साथ पुलिस और समाज की भूमिका पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन वह मानसिकता जो उनके प्रति बनी है वह आज भी समाप्त नहीं हो पाई। सरकारों ने समय-समय पर विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए योजनाएँ और संस्थागत व्यवस्थाएँ बनाई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पहलों की दिशा सकारात्मक है। लेकिन किसी योजना की सफलता उसके बजट या घोषणा से नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उसके वास्तविक लाभ से तय होती है। सवाल यह होना चाहिए कि कितने परिवार वास्तव में इन योजनाओं से जुड़े और कितने अभी भी व्यवस्था की पहुंच से बाहर हैं। हमें विकास की अपनी परिभाषा पर भी पुनर्विचार करना होगा। क्या विकास का अर्थ हर घुमंतू परिवार को स्थायी बनाना है? या विकास का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति घुमंतू जीवन जीते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के अधिकार से वंचित न हो? यदि कोई समुदाय अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण गतिशील जीवन जीता है, तो नीति को उसकी जीवन-पद्धति के अनुरूप बनना चाहिए, न कि उसे जबरन एक ही सामाजिक ढांचे में फिट करना चाहिए।

घुमंतू और विमुक्त समुदायों के संदर्भ में 'कल्याण' से आगे बढ़कर 'अधिकार' की भाषा अपनाने की जरूरत है। उन्हें दया या सहायता के पात्र के रूप में देखने के बजाय समान अधिकार वाले नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा उनका अधिकार है, स्वास्थ्य उनका अधिकार है, सुरक्षित आवास उनका अधिकार है, सम्मानजनक रोजगार उनका अधिकार है और सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान के साथ जीवन जीना। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यदि इन समुदायों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और मुख्यधारा में शामिल होने की चुनौती आज भी उनके सामने खड़ी है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह विकास किसके लिए हो रहा है? इस विकास की धारा में देश के आदिवासी कहाँ हैं? दलित कहाँ हैं? और वे तमाम घुमंतू-अर्धघुमंतू समुदाय कहाँ हैं, जिन्हें आज भी अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? विडंबना यह है कि आज भी कहीं कोई आपराधिक घटना होती है, तो शक की पहली उंगली इन्हीं समुदायों की ओर उठती है। पुलिस की पूछताछ और प्रताड़ना का सामना सबसे पहले उन्हें करना पड़ता है। यानी आजादी ने देश को तो स्वतंत्र किया, लेकिन क्या इन समुदायों को सामाजिक कलंक, संदेह और भेदभाव से वास्तव में मुक्ति मिल पाई है? यदि नहीं, तो हमें अपने विकास के दावों और उनकी दिशा पर गंभीरता से सवाल उठाने होंगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

विजी श्रीवास्तव

लेखक व्यंग्यकार हैं।

कुत्तों की नसबंदी का धारा प्रवाह विरोध

नगर निगम की गाड़ी, जाल, बोरी उन्हें कहां ले जा सकती है - यह उन सबको अच्छी तरह पता है। वे भले ही इन्सानी भाषाओं को न पढ़ पाएं किन्तु उनके भावों को अवश्य ही भांप लेते हैं। जैसे ही यह माहौल बनते देखते हैं, मौहल्ले के सारे कुत्ते दुम दबा कर भाग खड़े होते हैं। जो कुत्ते अभी अभी युवा हुए हैं, भागने वालों में सबसे आगे होते हैं। बीच बीच में दूसरे कुत्तों को भों-भों कर, आगाह करते। लेकिन उनके बीच कुछ जांबाज कुत्ते भी हैं, जो इन सबसे बेख़ौफ हैं। नगरनिगम की गाड़ी लौट जाने के बाद वापस आए मोहल्ले के कुत्तों को संबोधित करते हुए एक लीडर कुत्ता, सामान्य वर्ग के कुत्ते से बोला-

'तू भागा क्यों रे?'

'अरे भाई, आपको पता तो है- नसबंदी करने वाले आए थे!'

'तो?'

तो क्या? सरकार आजकल बड़ी सख्त है, किसी के बाप की नहीं सुनती। पता नहीं क्या कि क्या कर दें!

लीडर ने समझाया–'सरकारी काम है इसीलिए तो घबराने की जरूरत नहीं। सरकारी काम होते ही काम चलाऊ हैं। मेरे पिता की भी नसबंदी हुई थी।'

'फिर?'

'फिर क्या? उसके बाद उन्होंने जाने कितनों की गोद हरी की। मैं भी उनकी नसबंदी के बाद की देन हूँ !' -कहते हुए वो थोड़ा सा शर्मा भी गया।'

उनकी बातों को सुनकर कुछ और कुत्ते पास खिसक आए थे। एक और कुत्ते ने सरकारी नसबंदी विभाग का गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया 'पता है, पशु चिकित्सक लोग क्या कह रहे थे- इस शहर में जितने कुत्ते नहीं है, उससे ज्यादा की नसबंदी हो चुकी है, कागज पर। हमारी नसबंदी से खूब चांदी काटी जा रही है उधर।'

इस बात को कोट करके एक कुतिया ने पूछा-नसबंदी क्या कागज पर होती है?

एक वरिष्ठ कुकुर चिन्तक ने कहा-'मैं तो लगातार अफसरों बंगलो पर रहा हूं, नसबंदी ही नहीं, तमाम सारे सरकारी काम, कागजों पर ही होते हैं।'

'कागज पर हो या आपरेशन टेबल पर, सरकारी लोगों का कुछ भरोसा नहीं। करने कुछ चलते हैं, कर कुछ डालते हैं।'

'तुम बिल्कुल फिक्र न करो। वहां डॉक्टर होते हैं....डॉग लवर और उनमें फरक होता है।'

'मेरा मतलब है कि आजकल किडनी, लीवर, हार्ट और कोई भी अंग सुरक्षित नहीं है। कब क्या गायब हो जाए, हम तो किसी को बता भी नहीं सकेंगे।'

'हमारे अंग लेकर वो करेंगे ही क्या? वे मनुष्य हैं, हम कुत्ते हैं....'

'यही तो डर है, हम सचमुच के कुत्ते हैं- वे बहुत कुत्ती चीज हैं।'

'लेकिन यार !' उसने कहा- 'हमें आपस में एक-दूसरे को कुत्ता नहीं कहना चाहिए। डॉग लवर्स बुरा मान जाएंगे।'

'तो क्या कहें?'

'श्वान।'

'इससे क्या हमारी शान बढ़ जाती है?'

'पता नहीं। लेकिन सभ्य समाज में कुत्ता कहना असभ्यता और श्वान कहना संवेदनशीलता माना जाता है।'

'सभ्यता का 'स' भी पता है उन्हें। हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए आतुर होने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक लेते एक बार। इंडिया में ही अकेले डेढ़ अरब होने जा रहे हैं। एक बार बोलते हैं सुव्यवस्थित रहना है तो आबादी कन्ट्रोल करो, दूसरी तरफ कहते हैं सुरक्षित रहना हो तो आबादी बढ़ाओ। बेचारा आदमी, रसोई गैस के बटनों की तरह हाई और लो फलैम पर सिंकता रहता है।'

सीनियर कुत्ता थोड़ा गंभीर हुआ–'सच कहूँ तो हमारे और उनके बीच नंगेपन की प्रतियोगिता जैसी चल रही है। फिर भी आदमी अपनी हवस को भूलकर हमारी नसबंदी के पीछे पड़ा है। जबकि उन्होंने अपनी यौन इच्छाओं और संबंधों के इतने रूप स्वीकार कर लिए हैं कि हमें तक शर्म आ जाए।'

दूसरा आहत कुत्ता बोला–'बिल्कुल! वे बच्चियों को नहीं छोड़ते, दिव्यांगों को नहीं छोड़ते, मानसिक रूप से असहाय लोगों तक को नहीं छोड़ते। लेकिन हमारी प्रजाति ही उन्हें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी दिखाई देती है!'

दो बूजुर्ग कुत्ते कुछ क्षण एक-दूसरे को देखते रहे। फिर उन्होंने एक साथ कहा– 'राम राम राम!'

एक और सजग कुत्ता बोला– 'बहुत निष्ठुर होते हैं मनुष्य। अपनी ही संतानों को झाड़ी में फैंक देते हैं, गला घोंट देते हैं, गर्भपात करवा कर भ्रूण हत्या ही कर देते हैं। खुद की गलती से छुटकारा पाने की शराफत देखो इनकी...गर्भपात की परमीशन के लिए कानून, अदालत और अस्पताल के दरवाजे तक पीटने लग जाते हैं।'

इतने में महाविद्यालय के कैंटीन में आने जाना वाला एक और कुत्ता बीच में कूद पड़ा–'हमें कुत्तों की नसबंदी के खिलाफ अपने जेन-जी को आगे लाना चाहिए।'

'तेरे हिसाब से जेन-जी कौन है?'

'हमारे साल भर वाले पिल्ले...'

'अरे पागल है क्या? एक बरस से कम की उम्र में तो हमारे बच्चे बाप बनने लग जाते हैं। आंदोलन करने चलेंगे तो वहीं पर मामला उलट जाएगा। हमारे जेन-जी पिल्लों के व्याभिचारी प्रदर्शन से आदमी को हमारी नसबंदी करने की जरूरत और ज्यादा नजर आने नहीं लगेगी ?'

'यही तो समस्या है। तुम्हारी भी और हमारी भी।'

एक अन्य सम्भ्रान्त किस्म का कुत्ता बोला–'अंकल, मनुष्य क्या सोचता है- कुत्तों की नसबंदी कर वह अपने समाज के 'कुतत्वों' पर भी नियंत्रण कर पाएगा?'

जवाब सरकारी दफ्तर में फाइलों के बीच सोने वाले कुत्ते की ओर से आया- -'आदमी किसी समस्या को निपटाने के लिए योजना बनाता है। फिर उसे सफल बनाने के लिए नई योजना बनाता है। वो भी असफल हो जाए तो समिति और आयोग। फिर आयोग से निकलती है नई रिपोर्ट...'

'और रिपोर्ट से क्या निकलता है?'

'किसी छोटे-मोटे का दोष....'

बातें निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थीं। अन्ततः विद्रोही तैवर अपनाकर सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि मनुष्यों द्वारा कुत्तों की नसबंदी के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन जरूर करना है। तब उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से एक खंबे को मनुष्यों की निष्ठुरता का प्रतीक माना और एक एक कर टांग उठाते अपने विरोध दर्ज कराने लगे।

न्याय और कानून

- विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

कृत्रिम बौद्धिकता और न्याय-निर्णयन की निष्पक्षता

न्यायालय एआई को पूरी तरह नकारता नहीं है। इसके बजाय, उसका कहना है कि फैसला लेने की प्रक्रिया पूरी तरह और हर हाल में इंसानी नियंत्रण में होनी चाहिए। हर चरण पर इंसान की भागीदारी जरूरी है। इसलिए चिंता तकनीक के विकास को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि बिना किसी नियम-कानून के इस पर निर्भरता धीरे-धीरे इंसानी समझ-बूझ और फैसले लेने की अनुशासित प्रक्रिया की जगह ले सकती है। न्यायालय की सोच सिर्फ सटीकता तक सीमित नहीं है। फैसला लेने की प्रक्रिया में तथ्य और कल्पना, सच और झूठ और न्याय और अन्याय के बीच फर्क करना जरूरी होता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा रमेश सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और अन्य मामले में न्यायिक कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से जुड़ी प्रक्रियात्मक और संस्थागत चिंता पर बात की है। यह अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य चिंता यह थी कि फैसला करने वाली अथॉरिटी ने ऐसी सामग्री पर भरोसा किया जो असल में मौजूद ही नहीं थी, सामग्री मनगढ़ंत थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थी। उसे ऐसे माना गया जैसे वह कोई बाध्यकारी न्यायिक नजीर हो। इस फैसले में माना गया है कि एआई में रोजमर्रा के और दिमागी, दोनों तरह के काम करने की क्षमता आ गई है। साथ ही, काम में तेजी और बेहतर नतीजे पाने के लिए पेशेवर लोग तेजी से इसका इस्तेमाल करने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि, न्यायालय ने तकनीकी मदद और तकनीकी तौर पर किसी चीज की जगह लेने के बीच फर्क बताया है। न्यायालयों ने हमेशा से ही न्याय व्यवस्था में मदद के तौर पर तकनीक को अपनाया है, लेकिन एआई अलग है। क्योंकि यह इंसानी सोच, तर्क और फैसला लेने की प्रक्रिया का विकल्प बन सकता है।

यह फर्क ही इस फैसले का मुख्य आधार है। न्यायालय ने एआई को पूरी तरह नकारता नहीं है। इसके बजाय, उसका कहना है कि फैसला लेने की प्रक्रिया पूरी तरह और हर हाल में इंसानी नियंत्रण में होनी चाहिए। हर चरण पर इंसान की भागीदारी जरूरी है। इसलिए चिंता तकनीक के विकास को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि बिना किसी नियम-कानून के इस पर निर्भरता धीरे-धीरे इंसानी समझ-बूझ और फैसले लेने की अनुशासित प्रक्रिया की जगह ले सकती है। न्यायालय की सोच सिर्फ सटीकता तक सीमित नहीं है। फैसला लेने की प्रक्रिया में तथ्य और कल्पना, सच और झूठ और न्याय और अन्याय के बीच फर्क करना जरूरी होता है। फैसले के अनुसार, यह क्षमता दिमाग की सोच-समझ कर, अनुशासित और व्यवस्थित ट्रेनिंग के साथ-साथ असल जिंदगी के अनुभव और दूरदर्शिता से विकसित होती है। इस दिमागी काम को किसी और को सौंपने से उस क्षमता के कमजोर होने का खतरा है जिस पर फैसला लेने की प्रक्रिया टिकी होती है। न्यायालय फैसला लेने की प्रक्रिया में इंसानी सूझबूझ को सबसे अहम मानता है।

सबसे जरूरी मुद्दा एआई 'हैलुसिनेशन' (भ्रम) का था। यानी किसी प्रॉम्प्ट के जवाब में ऐसी जानकारी बनाना जो असल में मौजूद ही नहीं है या मनगढ़ंत है। न्यायालय ने जानबूझकर हैलुसिनेशन की तकनीकी वजह और उसके समाधान का काम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया है। न्यायालय की चिंता कानूनी है। ऐसी जानकारी को कानूनी नजीर के तौर पर पेश करना या उस पर भरोसा करना। न्यायालय ने इस मामले में बहुत सख्त रुख अपनाया है। बिना पुष्टि किए एआई से बनी नजीरों को बनाने, उनका हवाला देने या इस्तेमाल करने के मामले में न्यायालय 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाता है। यह वकील बिना पुष्टि किए ऐसी जानकारी का हवाला देता है, वह कदाचार करता है। इसी तरह, मनगढ़ंत या हैलुसिनेशन वाली जानकारी पर न्यायालय का भरोसा करना भी एक गंभीर चूक है। सबसे अहम बात यह है कि न्यायालय ने कहा है कि ऐसी जानकारी पर आधारित फैसला कानून की नजर में कोई फैसला नहीं है, चाहे उस जानकारी का फैसला लेने की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ा हो या परोक्ष। फैसला लेने की प्रक्रिया में ऐसी जानकारी का जरा सा भी हिस्सा शामिल होना फैसले को रद्द करने के लिए काफी है, क्योंकि यह न्याय-निर्णयन की पवित्रता का उल्लंघन करता है।

इस मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कर्ज और डिफॉल्ट का पता चलने के बाद, कॉर्पोरेट गारंटर एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ सेक्शन सात के तहत दायर अर्जी को स्वीकार कर ली थी। अपील करने वाले ने न्यायाधिकरण के सामने इस आदेश को चुनौती दी और डीमर्जर (कारोबार अलग होने) व अमलगमेशन (कंपनियों के विलय) के असर और कॉर्पोरेट गारंटी के बने रहने को लेकर तर्क दिए। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने अपील खारिज कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की जांच से पता चला कि अधिकारियों ने छह कथित पुराने फैसलों का सहारा लिया था। इनमें से कुछ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। कुछ असली फैसले थे लेकिन उनके

साथ ऐसे पैराग्राफ जोड़े गए थे जो असल में थे ही नहीं। एक फैसला गलत तरीके से पहचाना गया था।

प्रतिवादियों के हलफनामे में यह भी कहा गया कि उनके वकील ने न्यायालय में इन फैसलों का हवाला नहीं दिया था और ये कथित पुराने फैसले खुद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (फैसला करने वाली अथॉरिटी) की रिसर्च से मिले थे। इसके बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने इस सामग्री की ठीक से जांच-पड़ताल नहीं की। इसलिए समस्या सिर्फ वकील द्वारा बिना जांचे-परखे किसी फैसले का हवाला देने की नहीं थी। यह समस्या खुद फैसला करने की प्रक्रिया के दौरान हुई। इससे पता चलता है कि एआई से बनी गलत जानकारी वकील की दलीलों के बिना भी किसी फैसले में शामिल हो सकती है।

न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ रोक लगाने वाले आदेश काफी नहीं हैं। जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमेटी बार के सदस्यों द्वारा नकली या मनगढ़ंत जानकारी को असली कानूनी नजीर के तौर पर पेश करने के मामले पर विचार करेगी। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाएगी और नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करेगी। न्यायालय के सामने पेश की गई हर नजीर की सच्चाई की जांच करने की व्यावहारिक कठिनाई को समझता है। न्यायिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारी और उन पर किए गए भरोसे पर चलती है। इसलिए, न्याय प्रक्रिया की ईमानदारी के लिए बार और बेंच, दोनों की मिली-जुली जिम्मेदारी जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने साफ किया है कि उसका फैसला एआई के सही इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता है। उसे आपत्ति नकली या मनगढ़ंत जानकारी को अदालती नजीर के तौर पर पेश करने या उस पर भरोसा करने से है। इस तरह, यह फैसला तकनीक विरोधी नहीं, बल्कि नियमन और सावधानी बरतने वाला है।

यह फैसला एक साफ न्यायिक सिद्धांत तय करता है। एआई फैसला लेने में मदद तो कर सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने वाली जानकारी की सच्चाई और कानूनी वैधता के लिए इंसानी जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे अहम दखल इस बात पर जोर देना है कि मनगढ़ंत मिसाल कोई मामूली तकनीकी गलती नहीं है। एक बार फैसला लेने में

इसका इस्तेमाल हो जाने पर, यह फैसले की विश्वसनीयता को ही कमजोर कर देता है। यह फैसला खुलेपन और न्यायिक संयम का मेल है। यह ।प् को एक मददगार के तौर पर तो मानता है, लेकिन साथ ही इसकी पुष्टि, जवाबदेही और लगातार इंसानी नियंत्रण पर भी जोर देता है। इसका संदेश यह है कि असलियत की कीमत पर काम की तेजी या दक्षता हासिल नहीं की जा सकती। न्यायालय ने साफ किया है कि उस सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना बार (वकीलों) और बेंच (न्यायाधीशों) दोनों की मिली-जुली जिम्मेदारी है। फैसला लेने की प्रक्रिया में, किसी फैसले का अधिकार सिर्फ उसके फर्क पर ही नहीं, बल्कि उस जानकारी की सच्चाई पर भी निर्भर करता है जिससे वह तर्क निकला है। हालांकि, प्रशासनिक काम और ड्राफ्टिंग अक्सर निचले अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं, लेकिन मामलों का विश्लेषण करना, उनके तथ्यों को समझना, कानून की व्याख्या करना और कानूनी तर्क तैयार करना। ये मुख्य न्यायिक काम हमेशा से कानून बनाने वालों और प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी जिम्मेदारी रहे हैं जिन्हें किसी और को नहीं सौंपा जा सकता।

कजरी तीज पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

परंपरा के झूले पर सवार भारतीय संस्कृति

साधना, त्याग और अटूट संकल्प के बाद भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। इसी कारण तीज के पर्वों में शिव-पार्वती की पूजा दांपत्य जीवन की मंगलकामना से विशेष रूप से जुड़ी मानी जाती है। कजरी तीज पर महिलाएं शिव-पार्वती की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास, स्थायित्व और सुख-शांति की प्रार्थना करती हैं। कजरी तीज की तिथि को लेकर पंचांग की गणना महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 30 अगस्त को सुबह 9 बजकर 36 मिनट से प्रारंभ होकर 31 अगस्त को सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से तिथि-निर्णय में उदया तिथि को प्राथमिकता देने की परंपरा है।

भारतीय संस्कृति में त्योहार जीवन-मूल्यों, पारिवारिक संबंधों, आस्था और लोक परंपराओं के जीवंत प्रतीक हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट पर्व है 'कजरी तीज', जिसमें दांपत्य प्रेम, नारी की आस्था, तप, प्रकृति और लोक-संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। धार्मिक परंपरा में इस दिन विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं जबकि अविवाहित युवतियां मनचाहे एवं योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजा करती हैं।

कजरी तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। अनेक जन्मों तक उनकी साधना, त्याग और अटूट संकल्प के बाद भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। इसी कारण तीज के पर्वों में शिव-पार्वती की पूजा दांपत्य जीवन की मंगलकामना से विशेष रूप से जुड़ी मानी जाती है। कजरी तीज पर महिलाएं शिव-पार्वती की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास, स्थायित्व और सुख-शांति की प्रार्थना करती हैं। कजरी तीज की तिथि को लेकर पंचांग की गणना महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 30 अगस्त को सुबह 9 बजकर 36 मिनट से प्रारंभ होकर 31 अगस्त को सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से तिथि-निर्णय में उदया तिथि को प्राथमिकता देने की परंपरा है।

इस व्रत का सबसे प्रमुख पक्ष इसकी कठिन साधना है। अनेक क्षेत्रों में विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और दिनभर अन्न-जल ग्रहण नहीं करती। हालांकि व्रत की विधि और नियम क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्जला व्रत प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, अत्यधिक कमजोरी या चिकित्सकीय कारणों वाले व्यक्तियों को कठोर उपवास करने के बजाय अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। आस्था का उद्देश्य शरीर को संकट में डालना नहीं बल्कि आत्मसंयम और श्रद्धा की अनुभूति करना है। कजरी तीज की एक विशिष्ट पहचान सत्तू से जुड़ी है। इसी कारण इसे कई स्थानों पर सातुड़ी तीज कहा जाता है। परंपरा में सत्तू का उपयोग पूजा और व्रत के पारण से संबंधित अनुष्ठानों में किया जाता है। विवाहित बेटियों को मायके से कपड़े, श्रृंगार सामग्री, मिठाइयां और अन्य सुहाग-सामग्री भेजने की परंपरा भी अनेक क्षेत्रों में प्रचलित है। यह केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि बेटी और मायके के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने वाली सुंदर सामाजिक परंपरा है।

कजरी तीज की लोककथा भी अत्यंत मार्मिक है। कथा के अनुसार, एक निर्धन ब्राह्मण की पत्नी कजरी तीज का व्रत कर रही थी। पूजा के लिए सत्तू आवश्यक था लेकिन घर में उसे खरीदने के लिए धन नहीं था। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ब्राह्मण सत्तू की तलाश में निकला। अंततः वह एक साहूकार की दुकान में पहुंच गया। वहां वह कुछ देर बैठा रहा और नींद आ जाने के कारण दुकानदार के कर्मचारियों ने उसे चोर समझ लिया। पूछताछ में ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और पत्नी के व्रत के लिए सत्तू लाने की विवशता की पूरी बात सच-सच बता दी। उसकी सच्चाई और पत्नी के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर साहूकार ने उसे क्षमा कर दिया। उसने ब्राह्मण की पत्नी को अपनी बहन मानते हुए सत्तू के साथ नए वस्त्र, आभूषण, मेहंदी, काजल और धन भी दिया। इस लोककथा का संदेश स्पष्ट है कि सच्ची नीयत, दांपत्य प्रेम, करुणा और सहयोग जीवन में समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। लोककथाएं ऐतिहासिक प्रमाण नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक स्मृतियां और नैतिक संदेश हैं, इसलिए उनका महत्व उनके मूल्यबोध में निहित है।

कजरी तीज का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम कजरी लोकगीत हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, मिर्जापुर और वाराणसी सहित कई क्षेत्रों में कजरी गायन की समृद्ध परंपरा रही है। मानसून की फुहारों, बादलों, हरियाली, विरह, प्रेम और मिलन की भावनाओं को स्वर देने वाले कजरी गीत भारतीय लोकसंगीत की अनमोल विरासत हैं। वर्षा ऋतु में झूलों पर झूलती महिलाएं सामूहिक रूप से कजरी गीत गाती हैं। इन गीतों

में कभी प्रियतम से मिलने की आकांक्षा होती है, कभी मायके की याद तो कभी सावन-भादों की प्रकृति का उल्लास। इस प्रकार कजरी तीज नारी मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला सांस्कृतिक मंच भी बन जाती है। राजस्थान में तो कजरी तीज का उत्सव विशेष आकर्षण रखता है। बूंदी सहित अनेक स्थानों पर मेलों और लोकउत्सवों का आयोजन होता है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों और आभूषणों से सजती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं तथा पूजा-अर्चना के साथ लोकगीत, नृत्य और झूले का आनंद लेती हैं। इस अवसर पर परिवार और समुदाय एक साथ आते हैं। राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी कजरी तीज की अपनी-अपनी विशिष्ट लोकपरंपराएं हैं।

कजरी तीज को समझने के लिए इसे तीज पर्वों की व्यापक परंपरा से जोड़कर देखना भी आवश्यक है। वर्ष में हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज प्रमुख तीज पर्व माने जाते हैं। इन तीनों में माता पार्वती और शिव की आराधना तथा दांपत्य मंगल की भावना का महत्वपूर्ण स्थान है, हालांकि उनकी तिथियां, अनुष्ठान और क्षेत्रीय परंपराएं अलग हैं। अक्षय तृतीया को कुछ बोलचाल की परंपराओं में 'आखा तीज' कहा जाता है लेकिन इसे कजरी तीज के समान पर्व समझना उचित नहीं है। कजरी तीज मूलतः नारी की आस्था और दांपत्य जीवन के प्रति उसके समर्पण का पर्व है लेकिन इसका अर्थ केवल पति की दीर्घायु की कामना तक सीमित कर देना इसके व्यापक सांस्कृतिक स्वरूप को छोटा कर देगा। यह पर्व परिवार, मायके-ससुराल के रिश्तों, बहन-बेटी के स्नेह, सामुदायिक सहभागिता, लोकसंगीत और प्रकृति के प्रति भारतीय संवेदनशीलता को भी अभिव्यक्त करता है। झूले, मेहंदी, श्रृंगार, लोकगीत और सामूहिक पूजा इसके उत्सव पक्ष को जीवंत बनाते हैं जबकि व्रत और संयम इसके आध्यात्मिक पक्ष को गहराई प्रदान करते हैं।

आधुनिक समय में कजरी तीज का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। बदलती जीवनशैली में त्योहारों का स्वरूप भले बदल रहा हो लेकिन परिवार और संबंधों की गरिमा बनाए रखना आज भी उतना ही आवश्यक है। कजरी तीज हमें बताती है कि वैवाहिक संबंध केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, विश्वास, सम्मान,सहनशीलता, जिम्मेदारी और परस्पर सहयोग से निर्मित साझेदारी हैं। इसलिए इस पर्व की भावना को केवल स्त्री के त्याग तक सीमित करने के बजाय पति-पत्नी के पारस्परिक सम्मान और समान सहभागिता से जोड़ना चाहिए। कजरी तीज प्रकृति के उस उल्लास का भी पर्व है, जब वर्षा से धरती हरी चादर ओढ़ लेती है और वातावरण जीवन से भर उठता है। लोक गीतों में बादल और वर्षा, झूलों में उमंग और पूजा में आस्था, इन सबका संगम भारतीय संस्कृति की उस दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य स्वयं को प्रकृति और समाज से अलग नहीं मानता। कजरी तीज आस्था, प्रेम, संयम, नारी-शक्ति, पारिवारिक स्नेह और लोक संस्कृति का जीवंत उत्सव है। माता पार्वती की तपस्या से प्रेरणा लेकरयह पर्व दांपत्य जीवन में निष्ठा और विश्वास का संदेश देता है, वहीं कजरी गीत और झूले भारतीय लोकजीवन की सहज उमंग को स्वर देते हैं। बदलते समय में इसकी बाहरी परंपराएं भले परिवर्तित हों पर प्रेम, समर्पण, पारिवारिक एकता और मंगलकामना की इसकी मूल भावना सदैव भारतीय जीवन-संस्कृति को आलोकित करती रहेगी।

सरोकार

- डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

ग्रीन इंडिया मिशन फैल, 8 प्रतिशत ही रही उपलब्धि

कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश के 16 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2015-25 के दौरान कार्बन सीक्वेस्टरेशन का आकलन किया। कैग ने यह भी कहा कि 14 राज्यों ने कार्बन सीक्वेस्टरेशन का आकलन किया ही नहीं। इसलिए मिशन की जलवायु परिवर्तन पर वास्तविक असर मापा ही नहीं जा सका। इस ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत सन 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन सीओ2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया हैं। अक्टूबर 2015 में इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दिए गए। किन्तु मार्च 2025 दो राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने इसका पालन ही नहीं किया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कार्बन सोखने की मात्रा मापने के लिए घाटपुर और सोनहट में 2 फ्लक्स टावर लगाए। इन दोनों पर करीब साढ़े तीन करोड़ रूपए खर्च भी किए गए। 2020 में शुरू की गई इस व्यवस्था में सेंसर और अन्य तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण ये पूरा सिस्टम बेकार पड़ा है। कैग ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

बरसात के मौसम में पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ के नारे खूब बुलन्द होते हैं किन्तु असल में वास्तविक धरातल पर हालात बिल्कुल उलट है। देश में साल 2012 में शुरू किए गए ग्रीन इंडिया मिशन की 12 साल बाद भी उपलब्धि मात्र 8 प्रतिशत रही ! यानी लक्ष्य का 92 प्रतिशत काम करना बाकी रहा। यह तस्वीर और हालात अत्यन्त निराशाजनक और चिन्तनीय है। कैग के देश में 16 राज्यों के ऑडिट में उक्त तथ्य सामने आया है। इस मिशन के अन्तर्गत देशभर में 14 लाख हेक्टेयर में वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य तय किया गया। इसमें से 12 साल में केवल 1.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही यह काम किया गया। अर्थात लक्ष्य का मात्र 8 प्रतिशत ही प्राप्ति की जा सकी। इसी प्रकार देश में इस मिशन के अंतर्गत कार्बन सीक्वेस्टरेशन का आंकलन 16 राज्यों में से केवल 2 राज्यों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने ही किया। बाकी राज्यों ने तो ध्यान ही नहीं दिया।

मध्यप्रदेश राज्य की हालत देखे तो यहां ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत 2012 में 3,40,700 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें से मात्र 26,939 हेक्टेयर क्षेत्र में ही पौधारोपण किया गया। यानी यह लक्ष्य की 7.91 प्रतिशत ही उपलब्धि रही। अर्थात् 92.09 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति ही नहीं की जा सकी। मध्यप्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह पौधारोपण का बहुत हल्ला मचा। किन्तु वास्तविक स्थिति अत्यन्त गंभीर और चिंताजनक है।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश के 16 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2015-25 के दौरान कार्बन सीक्वेस्टरेशन का आकलन किया। कैग ने यह भी कहा कि 14 राज्यों ने कार्बन सीक्वेस्टरेशन का आकलन किया ही नहीं। इसलिए मिशन की जलवायु परिवर्तन पर वास्तविक असर मापा ही नहीं जा सका। इस ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत सन 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन सीओ2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया हैं। अक्टूबर 2015 में इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दिए गए। किन्तु मार्च 2025 दो राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने इसका पालन ही नहीं किया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कार्बन सोखने की मात्रा मापने के लिए घाटपुर और सोनहट में 2 फ्लक्स टावर लगाए। इन दोनों पर करीब साढ़े तीन करोड़ रूपए खर्च भी किए गए। 2020 में शुरू की गई इस व्यवस्था में सेंसर और अन्य तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण ये पूरा सिस्टम बेकार पड़ा है। कैग ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

कैग ने अपने ऑडिट के निष्कर्ष में यह भी बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन में सभी राज्यों में हर स्तर पर निगरानी में काफी कमियाँ रही। यह भी पता नहीं चल सका कि जीआईएम ने जलवायु परिवर्तन से निमटने में अपना कितना योगदान दिया है। कैग द्वारा मध्यप्रदेश में किए गए ऑडिट में यह भी पता चला कि 14 समितियों ने बिना कोई प्लान के ही काम कर दिया। प्रदेश के 8 संभागों में 70.67 करोड़ रूपये का भुगतान भी विभागीय स्तर पर कर दिया गया है। कैग की रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी 145 समितियों में से मात्र 5 समितियों ने ही सीए से ऑडिट कराया। बाकी समितियों ने ऑडिट कराने का कष्ट ही नहीं उठाया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में 444 हेक्टेयर में काम शुरू होना बताया गया, लेकिन कैग द्वारा की गई जांच में आरएफ-269 सहित अन्य साईट पर कई जगह हरियाली नहीं मिली। यही नहीं 68 हेक्टेयर की एक साईट पर कोई काम ही नहीं मिला। कैग ने इस हालात पर भी चिंता व्यक्त की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशक में मध्यप्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में वन विभाग का अनाप-शनाप विस्तार किया गया। जिन जिलों में जिला अधिकारी के रूप में केवल एक वन मंडलाधिकारी और संभाग स्तर पर वन संरक्षक पदस्थ रहते थे, वहीं संभाग स्तरीय पद को जिला स्तरीय बना दिया गया। अर्थात जिलों में वन मंडलाधिकारी की जगह वन संरक्षक पदस्थ किए गए। इसी प्रकार संभाग स्तर पर वन संरक्षक से उच्च पदों के अधिकारी पदस्थ किए गए। इसके साथ ही जिलों में और संभागों में अन्य अधिकारियों की भी पहले से अधिक तैनाती की जाने लगी। इसके बावजूद ग्रीन इंडिया मिशन के लक्ष्य और उपलब्धि आँखे खोलने वाली है। वन विभाग के अधिकारी अपने पदों के कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। इस ग्रीन इंडिया मिशन की हालत बता रही है कि देश में सभी राज्य पौधारोपण के प्रति अत्यन्त लापरवाह हैं। देश के 16 राज्यों में की गई ऑडिट में से एक भी राज्य में ऐसी उपलब्धि नजर नहीं आई जो उल्लेखनीय हो। यह स्थिति अत्यन्त गंभीर और चिंताजनक है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि जिन राज्यों में लक्ष्य की दयनीय उपलब्धि है, उन राज्यों के प्रदेश, संभाग व जिले स्तर के वन विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई करे, जो अपने कर्त्तव्य पालन में नाकाम रहे। इसके साथ ही राज्यों से इस बारे में सवाल जवाब तलब किए जावें और इस मिशन के लक्ष्य 2030 तक गंभीरतापूर्वक कार्य कर उन्हें लक्ष्य की पूर्ति करने के सख्त निर्देश दिए जाएँ, ताकि जिस अच्छे उद्देश्य के तहत ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया था उसकी प्राप्ति की जा सकी।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

आजकल की रईसी का आलम ही कुछ और है....

आज स्थिति यह है कि आम आदमी के लिए यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि उनके गृह ग्राम, नगर, कस्बे एवं शहर के सबसे बड़े सेठ कौन है ? दरअसल देखते ही देखते आम आदमी की क्रय शक्ति में इस कदर इजाफा हो चला है कि अब जीवन जीने के लिए केवल और केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही पर्याप्त नहीं है। वैसे आजकल के दौर में रोटी, केवल रोटी तक सीमित नहीं रही, कपड़ा भी केवल कपड़े तक सीमित नहीं रहा और मकान भी केवल मकान तक सीमित नहीं रहा।

बीते दौर में लगभग हर शहर, नगर, कस्बे एवं गांवों में कोई एक सर्वमान्य सबसे बड़े सेठ हुआ करते थे। जिन्हें बोलचाल की भाषा में नगर सेठ का दर्जा दिया जाता था। जाहिर है कि उनका रहन सहन और खान पान अन्यों की तुलना में उच्च स्तर को छुआ करता था। बड़ी हवेली, चमचमाती कार, लंबी-चौड़ी झक सफेद गादी और गोल मटोल तकिए वाली बैठक इनकी अति संपन्नता की कहानी बयां करती थी। कहीं-कहीं नगर सेठ की धार्मिक मनोवृति इस कदर प्रबल देखी जाती थी कि वे व्यक्तिगत तौर पर अपने सकल समाज के लिए मंदिर, धर्मशाला, कुआँ-बावड़ी आदि का निर्माण कर दिया करते थे। आमतौर पर वे ऐसे निर्माण को पूर्णता प्रदान नहीं करते थे अपितु 'लगभग पूर्ण अवस्था' तक ला दिया करते थे। आशय महज इतना होता था कि उनके संपूर्ण समाज की चाहे न्यूनतम से न्यूनतम लेकिन कुछ न कुछ वित्तीय सहयोग के रूप में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जिसके चलते सकल समाज का एक प्रकार से उक्त निर्माण के प्रति 'अपनेपन' का भाव जागृत हो सके। लेकिन बदलते दौर में अब यह दर्जा कहीं से कहीं तक कोई मायने नहीं रखता। यह स्थिति हर एक व्यापार व्यवसाय, उद्योग तथा शारीरिक और मानसिक श्रम शक्ति के बूते नगर सेठ की दौड़ में सहभागी बहुलता को रेखांकित करती है। आज स्थिति यह है कि आम आदमी के लिए यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि उनके गृह ग्राम, नगर, कस्बे एवं शहर के सबसे बड़े सेठ कौन है ? दरअसल देखते ही देखते आम आदमी की क्रय शक्ति में इस कदर इजाफा हो चला है कि अब जीवन जीने के लिए केवल और केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही पर्याप्त नहीं है। वैसे आजकल के दौर में रोटी, केवल रोटी तक सीमित नहीं रही, कपड़ा भी केवल कपड़े तक सीमित नहीं रहा और मकान भी केवल मकान तक सीमित नहीं रहा। रोटी और कपड़े को ही लीजिए, इसकी व्यवस्था सैकड़ो और हजारों रुपए ही नहीं अपितु इसके लिए तो लाखों रुपए भी कम पड़ सकते हैं। रहा सवाल मकान का तो लाखों के मकान अब करोड़ों को छूते जा रहे हैं। यही नहीं अपितु मकान के फर्नीचर की भी अलग-अलग श्रेणियां हो गई है। रसोई घर, बैठक कक्ष, अध्ययन कक्ष, बच्चों का कक्ष और आगंतुक मेहमान के लिए विशिष्ट कक्ष भी अलग-अलग होने लगे हैं। इसके लिए इन तमाम कक्षों में अलग-अलग तरीके के फर्नीचर भी आवश्यक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान दौर में दैनिक उपयोग तथा उपभोग की अनगिनत सुविधाएं एवं सामग्रियों का तो कहीं से कहीं तक कोई ओर-छोर ही नजर नहीं आता। आजकल छोटी से छोटी चीज के लिए भी बड़े से बड़े ब्रांड को पसंद किया जाने लगा है। ऊपरी तौर पर आम आदमी निरंतर महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त करता हैं। लेकिन आम आदमी के बीते दौर की तुलना में आजकल का रहन-सहन और जीवन स्तर हर तरीके से निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। इसलिए यह कहना तो सरासर बेमानी होगी कि आम आदमी विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। दरअसल आम आदमी यदि व्यथित हैं भी तो अपनी क्षमता से अधिक की चाहत के चलते स्वयं को दुखी कर रहा है। अन्यथा बाजार में तमाम तरह के संसाधन अपनी उपयोगिता के बारे में चाहे आम आदमी का ध्यान आकर्षित करते है। लेकिन आम आदमी को उसके लिए बाध्य तो कदापि नहीं करते। बीते दौर में टेलीफोन एक ऐसा संचार साधन था जो केवल परिजनों के लिए ही नहीं अपितु आसपास के तमाम रहवासियों के लिए भी उपयोग में आता था। वैसे इसके पूर्व तो एक वह भी जमाना था जब टेलीफोन सुविधा का विस्तार नहीं हुआ था और आवश्यक संदेश के लिए टेलीग्राम पर ही निर्भर रहा जाता था। वैसे उस दौर में किसी के नाम टेलीग्राम आने पर घर-परिवार में रोना गाना प्रारंभ हो जाता था। क्योंकि उस दौर में आमतौर पर निकट संबंधी की गंभीर बीमारी या मृत्यु की सूचना के सूचक के रूप में टेलीग्राम को माना जाता था। वैसे कभी-कभार ब्याह शादी में बुलावा या व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश भी टेलीग्राम द्वारा दिए जाते थे। कुल मिलाकर निरंतर नई खोज तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने दुनिया भर के बाजार में तमाम तरह के भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान क्या दिया, हर किसी नई चीज की ओर लपकने का भाव जन-जन में व्याप्त होने लगा। आज स्थिति यह है कि तरीका चाहे उचित या अनुचित ही क्यों न अपनाया जाएं, हर कोई अपनी क्रयशक्ति बढ़ाने की दिशा में मशगूल है। यही कारण है कि सामाजिक परिवेश में तमाम तरह के अपराधों की बाढ़ आई हुई है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बीता दौर सुख शांति से परिपूर्ण था। तमाम तरह के अभाव के बावजूद मन का खजाना तो हमेशा हरा-भरा रहा करता था।

प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपये

भोपाल (नप्र)। कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों का आधुनिक तकनीक से जुड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि का अंतरण करेंगे। विद्यार्थियों को यह राशि 1 सितंबर को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित लैपटॉप क्रय के लिये राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें डिजिटल तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का संबल - प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 25 हजार रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों को कुल 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा।

कैट के व्यापारिक सम्मेलन में बोले विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर

मोदी जी के संकल्प और व्यापारी समाज के साथ से विकसित बनेगा भारत

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि व्यापार और व्यवसाय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े और व्यापारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों एवं रुकावटों का निराकरण होना आवश्यक है। हर बड़े सुधार के पीछे स्पष्ट संकल्प, साफ नीयत और अच्छी नीति की आवश्यकता होती है। व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीएसटी जैसे कर सुधार ले कर आए। यह बात ओर है कि इस प्रक्रिया के आरंभ में कुछ कठिनाइयां आईं लेकिन यह सिद्ध हुआ कि कठिनाई देश के व्यापक हित के लिए हो तो व्यापारी समाज और देश की जनता दोनों उसका सहयोग करते हैं। ऐसे ही पीएम मोदी जी संकल्प और व्यापारी समाज का साथ मिल कर विकसित भारत बनाएंगे। श्री तोमर आज विधानसभा परिसर स्थित मानसरोवर सभागार में आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल के माध्यम से देश के सामने आत्मनिर्भरता का बड़ा विचार रखा है।

मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, बल्कि एक विचार और जज्बा है, जिसे साकार करने के लिए संकल्प और परिश्रम की आवश्यकता है। लोकल फॉर वोकल का अर्थ केवल त्योहार पर स्थानीय उत्पाद खरीद लेना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को निरंतर प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि एक समय भारत में रेलवे के डिब्बों के अनेक पुर्जे विदेशों से आयात किए जाते थे। आज देश में वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्माण हो रहा है। यह भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मविश्वास और स्वदेशी शक्ति का उदाहरण है। देश की यह उपलब्धि सरकार के प्रयासों के साथ उद्योग और व्यापार जगत के योगदान का भी परिणाम है। जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से विकास केवल बड़े उद्योगों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा है। विकसित भारत के निर्माण में गाँव में बैठे गरीब व्यक्ति, छोटे व्यापारी, किसान, श्रमिक और सामान्य नागरिक सभी की भागीदारी आवश्यक है। कई बार छोटा व्यापारी सोचता है कि उसके अकेले के प्रयास से क्या बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। देश में बड़ा परिवर्तन तभी संभव है, जब छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी समझकर उसमें योगदान दे।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि कैट द्वारा स्थानीय उत्पादों और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी प्रकार की बड़ी प्रदर्शनी ग्वालियर में भी आयोजित की जाए और ऐसे आयोजन देशभर में होने चाहिए। इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा और छोटे व्यापारियों, कारीगरों तथा स्वयं सहायता समूहों को नई पहचान मिलेगी। इस अवसर पर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी. भरतिया, जी, विशिष्ट अतिथि कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल, राष्ट्रीय चेयरमेन श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, महिला विंग की श्रीमती संगीता पाटिल सहित संगठन के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आए व्यापारिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रमुख सचिव ऊर्जा ने किया एमपी ट्रांसको के 220 केवी सब स्टेशन रोंसरा का निरीक्षण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह ने नरसिंहपुर जिले के भ्रमण के दौरान मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के 220/132/33 केवी अति उच्च दाब सबस्टेशन रोंसरा, नरसिंहपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने सब स्टेशन की व्यवस्थाओं, विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा संचालित कार्यों की जानकारी लेकर एम पी ट्रांसको के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री सिंह ने सब स्टेशन की आपरेशन एवं मेंटेनेंस गतिविधियों तथा विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता का जायजा लिया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए विद्युत कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

सब स्टेशन पहुंच मार्ग के सुधार के दिए निर्देश- नरसिंहपुर बाईपास निर्माण के कारण 220 केवी सब स्टेशन रोंसरा के पहुंच मार्ग में उत्पन्न हुई समस्याओं पर प्रमुख सचिव ऊर्जा ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्य अभियंता (टेस्टिंग) श्री एम.वाय. मंसूरी से चर्चा करते हुए कहा कि यदि वर्तमान में सबस्टेशन तक सामान्य वाहनों की पहुंच में कठिनाई हो रही है, तो किसी आकस्मिक स्थिति में बड़े पॉवर ट्रांसफार्मर एवं अन्य भारी उपकरणों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समीपस्थ नाले पर निर्मित पुल के पुनर्निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सब स्टेशन की एप्रोच रोड के शीघ्र सुधार के भी निर्देश दिए।

आगामी रबी सीजन की तैयारियों एवं ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क की समीक्षा

प्रमुख सचिव ऊर्जा ने जबलपुर एवं पिपरिया के मध्य स्थित इस महत्वपूर्ण सब स्टेशन के लोड प्रबंधन एवं वोल्टेज प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं तथा संभावित लोड का पूर्वानुमान तैयार किया जाए।

इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता (टेस्टिंग) श्री एन.एस. लोधी से एमपी ट्रांसको के ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) नेटवर्क, उसके लीजिंग कार्य तथा संबंधित सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क कीव उपलब्धता अधिकतम बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए जाएं, जिससे सेवा प्रदाताओं एवं उनके उपभोक्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोक

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों के निधन पर शोक व्यक्त कर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है।

मध्यप्रदेश लेखक संघ के साहित्यिक सम्मान घोषित

भोपाल। मध्यप्रदेश लेखक संघ के वार्षिक सम्मानो की घोषणा कर दी गई है। संघ की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में आज सम्पन्न हुई। वार्षिक सभा में प्रादेशिक कोषाध्यक्ष सुनील चतुर्वेदी ने वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र गट्टानी ने चयन समिति द्वारा चयनित एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वर्ष 2026 के साहित्यिक सम्मानों की घोषणा की । सभा में उपस्थित सम्मान हेतु चयनित साहित्यकारों का लेखक संघ पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया । सम्मानित सदस्यों की सूची इस प्रकार है -

पं.बटुक चतुर्वेदी अक्षर आदित्य सम्मान -

श्री प्रभु दयाल मिश्र, भोपाल,

सारस्वत सम्मान -

शिव चौरसिया एवं डॉ. हरिमोहन बुधौलिया उज्जैन, अरविन्द चतुर्वेदी स्मृति साहित्य सेवी सम्मान -जगदीश कौशल, भोपाल,

राधेश्याम द्विवेदी ऐतिहासिक/पौराणिक उपन्यास/ नाटक सम्मान -

कुमार सुरेश, भोपाल, डॉ. सरोजिनी कुलश्रेष्ठ कहानी सम्मान -

डॉ. संतोष श्रीवास्तव, भोपाल,

डॉ. पुष्पा चौरसिया श्रेष्ठ गीतकार सम्मान -

श्रीमती मधु शुक्ला, भोपाल, इंजी. प्रमोद शिरढोणकर विरहमन स्मृति राष्ट्र प्रेरणा सम्मान-

शंभू सिंह मनहर, खरगोन,

शिव शंकर यात्रा वृतान्त सम्मान -

संतोष मोहन्ती दीप, इन्दौर, सुधा सावित्री श्रेष्ठ बुन्देली साहित्यकार सम्मान -

मनीराम शर्मा, दतिया,णसरदार दिलजीत सिंह रील व्यंग्य सम्मान -

महेन्द्र अग्रवाल, शिवपुरी,स्व. जैतराम धमेनियाँ स्मृति छांदस रचनाकार सम्मान - अशोक तिवारी अमन, भोपा स्व. कैलाश चन्द्र जायसवाल सुदीर्घ साहित्य साधना सम्मान -

राजेन्द्र शर्मा अक्षर, भोपाल मदन मोहन चतुर्वेदी साहित्यिक/सांस्कृतिक पत्रकारिता सम्मान गौरीशंकर शर्मा गौरीश, संपादक कला वीथिका भोपाल अशोक चन्द्र दुबे अशोक, संपादक विप्र वाणी, भोपाल देवेन्द्र जोशी हिन्दी/ मालवी साहित्य सेवी सम्मान - राजेश रावल, उज्जैनसंतोष तिवारी समीक्षा सम्मान -

डॉ. शोभा सिंह, गुना एवं डॉ. संध्या सिलावट, इन्द पं. बृज वल्लभ आचार्य संस्कृतज्ञ सम्मान संजय द्विवेदी, ध्रुवा, भोपाल, शरण चौबे गीतकार सम्मान -

राम प्रकाश तिवारी, उज्जैन मेहमूद जकी ग़ज़ल सम्मान - राज कुमार कोरी, बैतूल. पुष्कर सम्मान - डॉ. रश्मि दीक्षित, खंडवा, देवकी नंदन माहेश्वरी सम्मान कुमार चन्दन, भोपाल कस्तूरी देवी चतुर्वेदी लोकभाषा सम्मान -

छोगालाल कुमरावत, खरगोन, हरीश निगम स्मृति मालवी भाषा सम्मान -

डॉ. श्रीकृष्ण जोशी, उज्जैन, काशी बाई मेहता लेखिका सम्मान

श्रीमती नीता सक्सेना, भोपाल, कमला चौबे स्मृति लेखिका सम्मान - श्रीमती सुबोध चतुर्वेदी, ग्वालियर,

अमित रमेश शर्मा मंचीय हास्य व्यंग्य कवि सम्मान -

राज कुमार वर्मा, इन्दौर,राम पूजन मलिक नवोदित गीतकार सम्मान -

अंशुल जैन, इन्दौर, मालती वसंत बाल साहित्यकार सम्मान -

डॉ. विनीता सिंह चौहान, इन्दौर,

उत्कृष्ट इकाई सम्मान -

टीकमगढ़ इकाई,

श्री गट्टानी ने बताया कि सम्मान समारोह वर्षान्त में उपयुक्त तिथि को भोपाल में आयोजित किया जायेगा । प्रारंभ में संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष श्री ऋषि श्रंगारी ने स्वागत वक्तव्य दिया तथा अंत में प्रादेशिक उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने आभार व्यक्त किया ।

राखी की डोर भरोसे की होती है, चुनावी वादों की नहीं, पहले लाड़ली बहनों के भरोसे का हिसाब दें शिवराज जी : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल करते हुए कहा कि राखी की डोर भरोसे की होती है, चुनावी वादों की नहीं। इसलिए सबसे पहले प्रदेश की लाड़ली बहनों के भरोसे का हिसाब दीजिए। श्री पटवारी ने कहा कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, तब प्रदेश की लाखों लाड़ली बहनें भाजपा सरकार से अपने उस वादे का जवाब मांग रही हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। चुनाव से पहले श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहनों से रू. 3,000 प्रतिमाह देने का वादा किया था। बहनों ने भरोसा किया, भाजपा को सत्ता मिली, लेकिन सत्ता मिलते ही वही वादा पीछे छूट गया। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि बहनों के खातों में 3,000 नहीं पहुंच रहे हैं और किस्त 1,500 पर ही अटकी हुई है। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करने वाली भाजपा सरकार अब उन वादों पर बात करने से भी बच रही है। बहनों को 3,000 देने का वादा कब पूरा होगा, इसका स्पष्ट जवाब सरकार को देना चाहिए। श्री पटवारी ने कहा कि सवाल सिर्फ पुरानी लाड़ली बहनों का नहीं है। नई पात्र बहनों के लिए पंजीयन भी बंद है। जिन महिलाओं की उम्र अब योजना के लिए निर्धारित सीमा में आ रही है, उनके लिए योजना का दरवाजा बंद क्यों कर दिया गया? क्या सरकार मानती है कि नई पात्र बहनों की आर्थिक जरूरतें नहीं हैं? क्या भाजपा के लिए बहनों का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सिर्फ चुनाव तक सीमित है? उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक जरूरतें किसी चुनावी कैलेंडर से तय नहीं होतीं। परिवार चलाने, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महिलाओं को निरंतर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में पात्र महिलाओं को योजना से बाहर रखना और नई पात्र बहनों का पंजीयन बंद करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। श्री पटवारी ने कहा कि बहनों का भरोसा तस्वीरों, विज्ञापनों और भावुक शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे किए गए वादों से जीता जाता है। शिवराज जी ने जिस वादे के नाम पर बहनों से विश्वास मांगा था, अब उसी वादे का हिसाब देने का समय है। उन्होंने मांग की कि भाजपा सरकार तत्काल स्पष्ट करे कि लाड़ली बहनों को 3,000 प्रतिमाह कब से दिए जाएंगे और नई पात्र बहनों के लिए पंजीयन कब शुरू किया जाएगा।

ग्वालियर-चंबल संभाग के शासकीय अस्पताल में पहली बार हुआ किडनी ट्रांसप्लांट

ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई मजबूती

● आयुष्मान योजना से निः शुल्क मिला उपचार

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सभी अंचलों में उच्चस्तरीय और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में ग्वालियर के गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ग्वालियर-चंबल संभाग के किसी शासकीय चिकित्सीय संस्थान में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट की सफल प्रक्रिया पूरी होना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस उपलब्धि पर गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी चिकित्सा टीम और विशेषज्ञों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जटिल और अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। अंग प्रत्यारोपण जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधा का ग्वालियर में शुरू होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के बड़े शहरों के साथ-साथ विभिन्न अंचलों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा और आयुष्मान योजना के माध्यम से निःशुल्क उपचार उपलब्ध होना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रविवार को ग्वालियर-चंबल संभाग के किसी शासकीय अस्पताल में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट की सफल प्रक्रिया पूरी की गई। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज और डोनर दोनों की हालत स्थिर है और चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इस उपलब्धि के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंग प्रत्यारोपण जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का नया अध्याय जुड़ गया है। छतरपुर निवासी श्री कृष्णकांत गुप्ता (60 वर्ष) की दोनों किडनियां खराब हो गई थीं। परिवार की सहमति के बाद उनकी पत्नी श्रीमती मीना गुप्ता (55 वर्ष) ने पति को किडनी दान करने की इच्छा जताई। इसके बाद मरीज और डोनर की आवश्यक मेडिकल जांच, काउंसलिंग, अनुकूलता परीक्षण तथा ट्रांसप्लांट से संबंधित अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद मरीज और डोनर को 29 अगस्त को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।

संक्षिप्त समाचार

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण

अशोक नगर (निप्र)। वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के दौरान आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषण टेकर एप एंट्री. सी.एम. हेल्पलाईन निराकरण, मैदानी स्तर पर गृह भेंट, कुपोषण चिन्हांकन, हितग्राहियों को दी जाने वाली सेवाओं में अनेक कमियों पाई जाती है। इन्हीं कमियों के पाए जाने पर मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम 2026 के तहत 7 अगस्त 2026 को श्रीमती जी.वी.रश्मि प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा परियोजना मुंगावली के भ्रमण के दौरान निर्देशित किया कि जिला अशोकनगर में सभी सेक्टर स्तर पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के छोटे-छोटे बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ट्रेनिंग थीम बेस्ड हों एवं प्रशिक्षण में पर्याप्त समय दिया जाए, ताकि प्रत्येक आंगनबाडी कार्यकर्ता पर ध्यान दिया जाए। इसी के आधार पर 12 अगस्त 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए। 20 अगस्त 2026 तक सेक्टर अशोकनगर ग्रामीण, बरखेडा गौड, नारायणपुर, राजपुर, रातीखेडा, सेमराहाट, शाढौरा, तूमैन में कुल 140 ओगनबाडी कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता को संपर्क एप व पोषण टेकर एप के एक-एक बिंदु पर विस्तार से समझाया गया। आंगनबाडी कार्यकर्ता को कौन से बिंदु पर किस समय एंट्री करना है यह बताया गया। समय सारणी के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र संचालन किस प्रकार करना है यह भी समझाया गया। प्रतिमाह बच्चों का वजन मापन करना, पोषण टेकर एप में एंट्री करना, सेम बच्चों की भूख की जांच करना, एन आर सी रैफर करना व ड्यू लिस्ट बनाना, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में पंजीयन व दी जाने वाली दवाओं के बारे में विस्तृत समझाया गया । आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को वजन लंबाई मापन करना समक्ष में समझाकर प्रत्येक कार्यकर्ता से वजन उचाई मापन करना सिखाया। प्री स्कूल एज्युकेशन के लिए भी कविता, कहानी, राष्ट्रीय गीत. राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में समझाया गया। विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का पंजीयन, छात्रवृत्ति व प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के पंजीयन के आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया गया । क्षेत्र की सी0 एम0 हेल्पलाईन के निराकरण के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण के प्रारंभ में एवं पश्चात् प्री एवं पोस्ट टेस्ट कर ऑनलाईन करवाये गये।

भिण्ड में गूंजा 'खेल की बात पीएम के साथ' का संदेश

भिण्ड (निप्र)। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी कक्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 भिण्ड एवं माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में 'खेलो इंडिया डायलॉगः खेल की बात पीएम के साथ' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर के खिलाड़ियों एवं युवाओं के साथ संवाद का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं मॉडरेटर की भूमिका अंशिका मिश्रा द्वारा प्रभावी ढ़ंग से निभाई गई। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा खेल के माध्यम से अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से देशभर के खिलाड़ियों एवं युवाओं को संबोधित करते हुए खेलों के प्रति समर्पण, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री के संवाद से उपस्थित युवाओं एवं विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह भदौरिया, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री अजीम खान, शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय क्रमांक-1 के प्राचार्य श्री पी.एस. चौहान, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्री धीरज सिंह गुर्जर एवं जिला युवा अधिकारी आशुतोष साहू उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने बानमौर के शासकीय जूनियर कन्या छात्रावास का किया निरीक्षण

मुरैना (निप्र)। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने शनिवार को बानमौर स्थित जूनियर बालिका अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री जांगिड़ ने छात्रावास के विभिन्न कक्षों एवं परिसर का निरीक्षण कर छात्राओं के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई, छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं तथा किसी प्रकार की समस्या के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं ने भी कलेक्टर से बातचीत कर अपनी आवश्यकताओं से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावास में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, स्नानागार, आवासीय कक्षों, विद्युत व्यवस्था एवं मच्छरों से बचाव के लिए खिड़कियों पर जाली सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छात्रावास की व्यवस्थाओं को बेहतर एवं व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

बिलौआ में लगा जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर

जमीन संबंधी विवाद निपटे तो घर के नजदीक ही बन गए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

शिविर में 126 आवेदन आए, अधिकांश का मौके पर निराकरण

संभागीय आयुक्त श्री खत्री एवं कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कराया समस्याओं का निराकरण

ग्वालियर (निप्र)। सूर्य प्रकाश को दिखाई नहीं देता और सूबेदार कुशवाह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। लम्बे समय से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की उम्मीद लगाए बैठे इन दोनों दिव्यांगों को उनके घर के नजदीक प्रमाण-पत्र बनाकर सौंपे गए। इसी तरह मिजाजीलाल, ज्योति व कमलेश के आयुष्मान कार्ड बन गए तो हरचरण कुशवाह, द्रोपदी, छुटिया व ग्यासोबाई के लंबित जमीन संबंधी प्रकरण का न केवल निराकरण हुआ बल्कि दस्तावेजों में अमल होकर खसरे की कॉपी भी उन्हें मिल गई। स्थानीय निवासियों की ऐसी ही तमाम समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। यहाँ बात हो रही है 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' के तहत शनिवार को बिलौआ में आयोजित हुए जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर की । पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी एवं नगर परिषद बिलौआ की अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी चौरसिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों की मौजूदगी में आयोजित हुए इस शिविर में संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत ने मौके पर ही समस्याओं का निराकरण कराकर आम जनता का सरकार के प्रति विश्वास मजबूत किया। शिविर में दिव्यांगों के प्रमाण-पत्र बनाने के लिये मेडीकल बोर्ड बैठा और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। साथ ही आधारकार्ड, आयुष्मानकार्ड व फार्मर आईडी भी शिविर में बनाई गईं। जिला स्तरीय शिविर में एसडीएम भितरवार श्री राजीव समाधिया सहित सहित विभिन्न विभागों के जिला व खंड स्तरीय अधिकारी जन समस्याओं के निराकरण के लिये पहुँचे थे। शिविर में कुल मिलाकर लगभग 126 समस्यायें प्राप्त हुईं। इनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष समस्याओं को सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जिससे इनके निराकरण की लगातार मॉनीटरिंग होती रहे। शिविर में उद्यमी संवाद हुआ। साथ ही मौके पर ही निराकृत समस्याओं के प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राजस्व अभिलेख में हुए अमल की कॉपी इत्यादि का वितरण भी किया गया।

स्थानीय उद्यमियों ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए : शिविर में स्थानीय एंटरप्रेन्योर (लघु उद्यमी) ने अपनी सफलता के अनुभव साझा कर अन्य युवाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यम स्थापित करने के लिये प्रेरित किया। बिलौआ निवासी श्री सोनू कुशवाह का कहना था कि पहले हम दूसरे की ऑटो पार्ट्स की दुकान पर मजदूरी पर काम करते थे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ने मुझे ऑटो पार्ट्स की दुकान का मालिक बना दिया है। इस योजना के तहत मिले 2 लाख रुपए के लोन से हमने अपनी दुकान खोली है और अब हम दो अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। अनुराग पाण्डे ने भी इसी योजना से 10 लाख रुपए का लोन लेकर आरओ प्लांट लगाया है। वे भी पहले दूसरे के प्लांट पर काम करते थे।

शिविर से पहले हुआ शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण

बिलौआ में जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर के शुरू होने से पहले कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बिलौआ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शासकीय सीनियर बालक छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं यहाँ के स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में पानी की निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश बिलौआ सीएमओ को दिए। साथ ही सम्पूर्ण परिसर में रोशनी की पुख्ता व्यवस्था करने पर बल दिया। कलेक्टर ने यहाँ के सरकारी स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाकर अनाधिकृत रास्ता बंद कराने के निर्देश तहसीलदार को दिए हैं। माध्यमिक विद्यालय की सातवीं कक्षा की कुछ छात्राओं को संस्कृत विषय की पुस्तक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और यहाँ के बीआरसी का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने स्कूल में एक शिक्षक की तरह बालिकाओं को अंग्रेजी में आवेदन एवं अन्य लेखन में कैपिटल लेटर महत्व समझाया। आंगनबाड़ी केन्द्र की व्यवस्थायें ठीक न पाए जाने पर उन्होंने यहां के सीडीपीओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं।

नगर परिषद बड़ौनी में आयोजित हुआ जन विश्वास शिविर

दतिया (निप्र)। जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आज शनिवार को आमजन को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सहज एवं सरल रूप से उपलब्ध कराने तथा नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर परिषद बड़ौनी में जन विश्वास शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री धीरू दांगी, नगर परिषद बडोनी अध्यक्ष श्री कमलेश अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह चावला, एसडीएम सुश्री सोनाली राजपूत सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर के दौरान जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री वानखडे द्वारा आधा सैकड़ा से अधिक नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं, शिकायतों एवं मांगों को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने विभिन्न मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान आवास योजना एवं समग्र आईडी से संबंधी शिकायतें अत्यधिक पाए जाने एवं शिकायतों के संबंध में सीएमओ नगर परिषद बडोनी द्वारा संतुष्टि पूर्वक जवाब ना दे पाने पर सीएमओ को फटकार लगाते हुए समस्त प्राप्त शिकायतों की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में आवेदनों का त्वरित निराकरण अभियान की सार्थकता : कलेक्टर मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर कदवाया में आयोजित

अशोक नगर (निप्र)। मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना ही अभियान की सार्थकता सिद्ध करता है। शिविर में आने वाले प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया गया। यह बात कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने शनिवार को जनपद पंचायत ईसागढ़ की ग्राम पंचायत कदवाया में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के अवसर पर कही। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य आमजन को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सरलता और सुगमता से उपलब्ध कराना है। शिविर में प्राप्त आवेदनों को लंबित रखने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण किया जाए। जिन प्रकरणों का मौके पर निराकरण संभव नहीं है, उनमें संबंधित विभाग समय-सीमा निर्धारित कर कार्यवाही पूर्ण करें तथा आवेदक को भी इसकी जानकारी दें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का संधारण व्यवस्थित रूप से किया जाए और निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनें और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सक्रियता से कार्य करें। शिविर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ स्वरोजगार एवं स्वंय के उद्योग स्थापित करने के लिये उद्योग संवाद का आयोजन किया गया है। कलेक्टर के नेतृत्व में शासन की योजनाओं के माध्यम से बैरोजगार युवकों को रोजगार मुहिया कराने तथा सीमित संसाधनों से उद्यमी बनाये जाने के लिये सभी आवश्यक प्रयास कर उन्हे सहायता दिलाना है। शिविर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री त्रिलोचन गौड ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत विकासखण्ड ईसागढ में जिले का चौथा शिविर यह ग्राम पंचायत कदवाया में आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 1587 विभिन्न शिकायतों का निराकरण कराया गया है। उद्यमियों ने किया जनसंवाद शिविर उद्यम संवाद के दौरान जनपद पंचायत ईसागढ के सफल उद्यमियों द्वारा जनसंवाद किया गया। साथ ही महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग श्री सतेन्द्र लोधा द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। हितलाभ का वितरण मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजस्व विभाग द्वारा बर्षा यादव, गोलू कुशवाह, कमला बाई, रमाशंकर, जितेन्द्र, रविकुमार एवं सतीश सोनी को नामातरण के प्रमाण पत्र तथा तथा अभिषा गुर्जर,आरिफ खान, सोविया यादव, श्यामबीर,कृतिका ओझा, तनुषा साहू, राधिका सहित अन्य हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्रों का वितरण अतिथियों द्वारा वितरित किये गए।

कलेक्टर वानखड़े ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौनी का किया निरीक्षण मरीज बनकर लिया डिजिटल हॉस्पिटल सेवाओं का अनुभव

दतिया (निप्र)। कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा आज शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौनी का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन को मुहैया कराये जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं मरीज बनकर आगामी समय में उपलब्ध कराई जाने वाली डिजीटल हॉस्पिटल सेवाओं का अनुभव लिया। उन्होंने अपना नाम और मोबाईल नम्बर बताकर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया तत्पश्चात् पृथक-पृथक बने कक्षों में जाकर रूटीन चैकअप कराते हुए चिकित्सक से परामर्श लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों के पंजीयन, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, चिकित्सक से परामर्श, जांच संबंधी प्रक्रिया तथा मरीजों को उपलब्ध होने वाली अन्य ऑनलाइन एवं डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में डिजीटल सेवा पूर्णतः प्रारंभ होने के पश्चात् मरीजों को इन सेवाओं का लाभ लेने में किस-किस प्रकार की परेशानी आ सकती है। कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद मरीजों एवं उनके परिजनों से भी चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल हॉस्पिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक मरीज को सरल, सहज और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का उपयोग मरीजों की सुविधा और उपचार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े तथा उन्हें आवश्यक जानकारी और सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने लेबर रूम, टीकाकरण कक्ष, वार्ड, एएनसी वार्ड, पीएनसी वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को स्वच्छता, मरीजों की सुविधा, सुचारु पंजीयन व्यवस्था तथा डिजिटल सेवाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर एवं सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीके वर्मा सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुना में 'खेलो इंडिया संवाद' का सफल आयोजन

गुना (निप्र)। क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुना में आज 'खेलो इंडिया संवाद' कार्यक्रम का भव्य और उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्राइस्ट स्कूल के उप-प्रधानाचार्य फादर जॉर्ज और जिला खेल अधिकारी श्री दुर्गेश चंद्र सक्सेना रहे। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री मनसुख मांडविया के स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर दिए गए प्रधानमंत्री के खेल-संबंधी भाषण के मुख्य अंशों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त वीडियो प्रदर्शित किया गया। इसके पश्चात, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि हमें ओलंपिक की अधिक से अधिक श्रेणियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण को याद करते हुए 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी और 5 से 15 वर्ष की आयु के उभरते खिलाड़ियों की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज शुरू करने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने 'विकसित भारत' के निर्माण में 'नशा मुक्त युवा' अभियान की अनिवार्यता और खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के अगले चरण में छात्रों और गुना के राष्ट्रीय स्तर के जूडो खिलाड़ी श्री मोनू कुशवाह के बीच एक प्रेरणादायक संवाद हुआ। उन्होंने अपनी चार साल की खेल यात्रा के अनुभवों और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के अपने संघर्षों को छात्रों के साथ साझा किया। जिला खेल अधिकारी श्री दुर्गेश चंद्र सक्सेना ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी पूरी सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

राखी के धागे ने बांधे रिश्ते, अपनों से दूर चेहरों पर खिल उठी मुस्कान

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने मंगलधाम वृद्ध आश्रम के रहवासियों के साथ मनाया रक्षाबंधन

ग्वालियर (निप्र)। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते में बंधे स्नेह का पर्व नहीं, बल्कि उन दिलों तक पहुंचने का अवसर भी है, जिन्हें अपनत्व की सबसे अधिक जरूरत है। इसी मानवीय भावना के साथ ग्वालियर में इस बार रक्षाबंधन का पर्व प्रशासनिक दायित्वों से आगे बढ़कर आत्मीय रिश्तों का पर्व बन गया। अपनों से दूर रह रहे बुजुर्गों और परिवार से दूर बालिकाओं के बीच पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनके साथ पर्व की खुशियां साझा कीं। नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर स्थित मंगलधाम वृद्ध आश्रम में उस समय माहौल भावुक हो गया, जब कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान वहां पहुंचीं। अपने साथ उपहार और मिठाइयां लेकर पहुंचीं कलेक्टर ने आश्रम में रह रहे भाइयों की कलाइयों पर स्नेहपूर्वक राखी बांधी और उन्हें उपहार भेंट किए। लंबे समय से परिवार से दूर रह रहे बुजुर्गों के लिए यह पल अपनेपन की कमी को भर गया। राखी के धागे के साथ मिले इस स्नेह ने उनके चेहरों पर खुशी ला दी। कलेक्टर श्रीमती चौहान के साथ एसडीएम मुरार श्री नरेश चंद्र गुप्ता एवं तहसीलदार श्री कुलदीप दुबे भी मंगलधाम पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आश्रम में रह रही बहनों से राखियां बंधवाईं और उन्हें उपहार भेंट कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। अधिकारियों की आत्मीयता से आश्रम का वातावरण पारिवारिक स्नेह से भर उठा।

जब बेटियों ने बांधी राखी, अधिकारियों ने निभाया भाई का रिश्ता

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की पहल पर जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी विभिन्न आश्रमों एवं बालिका संरक्षण गृहों में पहुंचकर रक्षाबंधन मनाया। अपर कलेक्टर श्री अनिल बनवारिया जेएएच परिसर स्थित माँ कैला देवी बालिका गृह पहुंचे। यहां बालिकाओं ने उन्हें राखी बांधी। उन्होंने बालिकाओं के साथ आत्मीयता से समय बिताया और उपहार भेंट किए।

तहसीलदार श्री महेश कुशवाह ने भी बालिकाओं से राखियां बंधवाईं और उन्हें उपहार भेंट कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। रक्षाबंधन के अवसर पर जिला प्रशासन की यह पहल संवेदनशीलता और अपनत्व का संदेश बन गई।

जिन कलाइयों पर राखी बांधने वाला कोई अपना दूर है, वहां प्रशासन के अधिकारी भाई बनकर पहुंचे। राखी के धागों ने यह एहसास कराया कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते। सच्चा अपनापन, सम्मान, संवेदना और स्नेह भी रिश्तों को जन्म देते हैं।

राइट क्लिक

बिलांगिंग': सियासी कड़वाहट में क्यों बदल रहा 'प्यार का एक सफर'

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी लिखित किताब 'बिलांगिंगः ए जर्नी ऑफ लव' (हिंदी में समझें तो 'रिश्तेः एक सफर प्यार का') को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा भारत में छापने से इंकार और इस संदर्भ में बाकायदा बयान जारी करना आप में असामान्य घटना है। इस बयान ने कई सवालों और संदेहों को हवा दे दी है। इस पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। अमूमन किसी पुस्तक का छापना न छापना लेखक और प्रकाशक के बीच की बात होती है और प्रकाशित पुस्तक में क्या, कैसा और किसके बारे में लिखा गया है, इसकी जिम्मेदारी दोनो की होती है। लेकिन ऐसी कौन-सी बातें अथवा तथ्यो हैं, जो प्रकाशक प्रकाशित नहीं करना चा हता था और जिसे लेखिका हर हाल में किताब में शामिल करना चाहती थी। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के दबाव में प्रकाशक ने ऐसा किया है, जबकि भाजपा ने इसका सिरे से खंडन किया है।

लेकिन यह पुस्तक विदेशों में छप रही है, ऐसे में जिन कथित 'विवादित बातों या तथ्योंस' की वजह से पेंगुइन ने किताब छापने से इंकार किया, वह सार्वजनिक तो ही जाएंगी। यह बात को प्रकाशक को भी मालूम होगी, फिर भी उसने पुस्तक छापने से इंकार क्यों किया, इसके पीछे क्या राज है? यह या तो पुस्तक के पब्लिक डोमेन में आने के बाद पता चलेगा या फिर स्वयं सोनिया गांधी इस बारे में कुछ बोलें तो खुलासा होगा। हैरानी की बात है कि पेंगुइन द्वारा पुस्तक प्रकाशन से इंकार के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अलबत्ता प्रकाशक के अधिकृत बयान और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स् से यही समझ आता है कि प्रकाशक ने लेखिका से पुस्तक में कुछ 'संपादकीय बदलाव' करने की बात कही थी, लेकिन सोनियाजी ने इंकार कर दिया। प्रकाशक 'पेंगुइन इंडिया' ने बयान में कहा कि वह 'बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ़ लव' की भारत में प्रकाशक नहीं है। किताब को प्रकाशित न करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि लेखिका ने संपादकीय बदलावों को ख़ारिज कर दिया था, यह परिस्थितियों को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। तथ्य की जांच करना और लेखक को ऐसे सुझाव देना जो किताब और लेखक दोनों के हित में हो, एक प्रकाशक के रूप में हमारा विशेषाधिकार और ज़िम्मेदारी दोनों है। पेंगुइन ने यह भी कहा कि वह लेखिका के साथ हुई गोपनीय चर्चाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। कंपनी के इस बयान से संदेह और गहरा गया है। गौरतलब है कि इस बहुप्रतीक्षित किताब का विमोचन 10 नवंबर को प्रस्तावित है।

वैसे यह भी दिलचस्प है कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवा दो हजार पहले रचित किताब 'मनुस्मृति' की आलोचना उसके कथित आपत्तिजनक अंशों के कारण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी एक किताब का प्रकाशन कथित रूप से रूकवाने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। पहले मामले में अभिव्यक्त विचारों को समाज में भेदभाव का कारण बताया जा रहा है तो दूसरे प्रकरण में पुस्तक में व्यक्त विचारों को 'हटवाने' को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से जोड़ा जा रहा है।

वैसे अंग्रेजी शब्द 'बिलांगिंग' के हिंदी में मायने हैं संपत्ति अथवा रिश्ते। सोनियाजी निश्चित रूप से किसके बारे में बताना चाह रही हैं। संभवतः यह रिश्तों के बारे में ही है। तो फिर रिश्तों को लेकर किताब में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से प्रकाशक को पीछे हटना पड़ा? जहां तक श्रीमती सोनिया गांधी की बात है तो वो भारत के नंबर एक राजनीतिक परिवार की बहू रही हैं और अपने पति और प्रियतम राजीव गांधी के साथ विवाह कर भारत में ही बस गईं। वो सीधे राजनीति में बहुत बाद में आईं, लेकिन भारत में 'इंदिरा युग के उदय से लेकर मोदी युग' तक के छह दशकों की उथल-पुथल भरी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक यात्रा की साक्षी, आलोचक और कई बार निर्णायक भूमिका में भी रही हैं। बावजूद तमाम व्यक्तिगत आलोचनाओं के सोनिया गांधी ने अपनी गरिमा को कायम रखा और प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी स्वेच्छा से त्याग किया। जाहिर है कि एक 'इनसाइडर' होने के नाते उनके अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन, निजी सुख-दुख और टिप्पणियों का अलग महत्व है। विदेशी महिला होकर भी उन्होंने जिस गरिमामय तरीके से भारतीयता को स्वीकार किया, उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। ऐसे में सोनियाजी अपने समकालीन इतिहास पर क्या सोचती हैं, उसे किस निगाह से देखती हैं, क्या महसूस करती हैं, यह निश्चित ही अहम है।

इसी संदर्भ में पेंगुइन की अमेरिका में सहयोगी कंपनी इम्प्रिंट अल्फ्रेड ए. नोफ ने पुस्तक के संदर्भ में सोनिया गांधी के हवाले से जारी बयान में साफ किया था कि 'मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम आख्यान उनकी प्रेरणाओं, उनके कार्यों और यहां तक कि उनकी मानवीय कमियों की सच्चाई तक पहुंच पाए हैं। छह दशकों से मैं जिन सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की गवाह रही हूं, मेरी कहानी पाठकों को उनका एक अनूठा नजरिया भी पेश करेगी।' उधर पेंगुइन के पुस्तक प्रकाशन से पीछे हटने पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशन से प्रकाशक का मना करना अत्यंत चिंता का विषय है। श्रीमती गांधी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति क्या लिखेगा और क्या नहीं, क्या यह प्रकाशक तय करेगा? प्रकाशक स्वयं यह कह रहा है या उस पर किसी का दबाव है? कुछ पत्रकारों ने भी कहा कि प्रकाशन व्यवसाय पर सरकार का दबाव है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने सवाल किया कि पेंगुइन इंडिया ने पहले 'एग्जाम वारियर्स' और आरएसएस से जुड़ी किताबें प्रकाशित की हैं, लेकिन अब सोनिया गांधी की किताब को लेकर उसका अलग रुख क्यों है? इन आरोपों के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में डर की कहानी बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के ही प्रवक्ता अजय आलोक ने परोक्ष रूप से प्रकाशक की तरफदारी करते हुए कहा कि किसी किताब में शामिल तथ्यों और आंकड़ों की जांच करना पब्लिशिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। पब्लिशर की ओर से फैक्ट चेक या बदलाव का सुझाव देना किसी राजनीतिक दबाव का सबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि खुद राहुल गांधी ने इस विवाद पर केवल इतना कहा कि इस वक्त संविधान बचाना ज्यादा जरूरी है बजाए इसके कि किस किताब में से क्या हटाया जा रहा है।

किताब में निश्चित रूप से विवादास्पद बिंदु क्या हैं, इसके बारे में अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिनकी चर्चा है, वो भारत का चीन के साथ सीमा विवाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और उसकी कार्यशैली तथा भाजपा की मातृसंस्था आरएसएस की भूमिका आदि हो सकते हैं। गौरतलब है कि श्रीमती सोनिया गांधी की इस बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 'बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव' के प्रकाशन का ऐलान 18 अगस्त 2026 को एक कार्यक्रम में किया गया था। इस संस्मरण को सोनियाजी के निजी और राजनीतिक जीवन का सबसे प्रामाणिक लेखा-जोखा बताया गया, जिसमें कई अनछुए पहलुओं को साझा किया गया है। हालांकि भारत में किसी प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक को छापने से पीछे हटने की यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन चूंकि इसका सीधा सम्बन्ध किसी व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन तथा राजनीति सरोकारों से भी है, इसलिए इस पर बवाल ज्यादा मचा है। कुछ लोग प्रकाशक की आड़ में लेखिका द्वारा कथित राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने के रूप में देख रहे हैं। यह सोनिया गांधी की निर्भीकता और दृढ़ता की ही एक और बानगी है। इसे लोकतंत्र में असहमति को दबाने की कोशिश के रूप में भी चित्रित किया जा रहा है। यह संदेह तो बना ही रहेगा कि आखिर किस दबाव में प्रकाशक एक संभावित बेस्ट सेलर किताब को भारत में छापने से बच रहा है? क्या इस किताब से माध्यहम से ऐसा कुछ उजागर होने वाला है, जो सत्ता प्रतिष्ठान को असहज कर सकता है, विचलित कर सकता है? हालांकि जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आएं, तब तक इसे अघोषित सेंसरशिप भी नहीं कहा जा सकता।

एक बात और। आजकल फिल्म हो या कुछ और, उसे पब्लिक डोमेन में आने से पहले विवादित बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, भले ही यह अंत में 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' साबित हो, लेकिन तब तक धंधा चंगा हो जाता है। यह किसी भी कृति की व्यावसायिक सफलता का आजमाया हुआ फार्मूला है। खबर है कि बिलांगिंग' का पहला ऑर्डर ही एक लाख प्रतियों का है। ऐसे में सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे और किताब का ऑर्डर भी बढ़ता रहेगा।

पहले मस्जिद और दरगाह हटाएं, इसके बाद हटेगा मंदिर

हिंदू संगठनों ने उज्जैन को किया जाम तो झुका प्रशासन, टला फैसला

उज्जैन (नप्र)। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक धार्मिक स्थल हटाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने सराफा क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर के बाहर धरना दिया। 5 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद भी जब प्रशासन ने बात नहीं मानी तो कार्यकर्ताओं ने शहर में पहुंचने वाले सभी प्रमुख पर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। यातायात व्यवस्था चरमराते ही प्रशासन को झुकना पड़ा और मंदिर हटाने का निर्णय तत्काल रोक दिया गया। इसके बाद धरना प्रदर्शन और जाम हट गया।

सड़क चौड़ीकरण का चल रहा कार्य- दरअसल, उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। कई मार्गों को चौड़ा कर दिया गया है। इन मार्गों के बीच में आने वाले धार्मिक स्थान को हटा भी दिया गया है। कुछ और मार्ग चौड़ा किए जा रहा है। इसी कड़ी में कंठाल चौराहा से गोपाल मंदिर तक का भी मार्ग चौड़ा हो रहा है। इस मार्ग में खड़े हनुमान मंदिर भी आता है। इसे हटाकर अन्यत्र जगह बनाना प्रस्तावित है। मंदिर को हटाने की कार्रवाई के लिए आज नगर निगम व पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा।

वाहनों की लग गई लंबी कतार- करीब एक घंटे तक चल चला जाम के कारण बाहर से आने वाले वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। तत्काल प्रशासन को झुकना

पड़ा और धरना प्रदर्शन और जाम खुल गया।

इस मार्ग पर प्रस्तावित है शाही सवारी- मामले में एसडीएम एल एन गर्ग ने कहा कि इस मार्ग से शाही सवारी प्रस्तावित है। खड़ा हनुमान मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। पुजारी से सहमति हो गई है। हिंदू समाज भी सहमत है, परंतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कुछ आपत्ति है। उनका कहना है कि सवारी के बाद मंदिर शिफ्ट हो, उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

हम मंदिर को नहीं हटने देंगे- वहीं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सह संयोजक विक्की राठौर ने कहा कि उन्हें जैसे ही पता चला कि मंदिर को हटाने के लिए प्रशासन का दल पहुंचा है तो वह भी मौके पर पहुंचे। हमने यह तय कर लिया है कि हम मंदिर को नहीं हटने देंगे। प्रशासन पहले मस्जिद और दरगाह हटाए। उसके बाद यह मंदिर हटेगा। यदि मंदिर हटाना है तो हमारी लाश पर बुलडोजर चले फिर मंदिर हटे। प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर शहर के कई मंदिर हटा दिए गए हैं, परंतु मस्जिद व दरगाह को नहीं हटाया गया है।

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिया धरना

वहीं, जैसे ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी तो वह भी एकत्रित हो गए। इसके बाद मंदिर के बाहर धरना दे दिया। करीब 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। यहां कार्यकर्ता मंदिर नहीं हटाने की मांग पर डटे रहे। काफी देर होने के बाद कार्यकर्ताओं ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर पहुंचने वाले प्रमुख मार्ग आगर रोड, इंदौर रोड, देवास रोड, उन्हेंल रोड, मक्सी रोड व बड़नगर रोड पर चक्काजाम कर दिया।

नरेला रक्षाबंधन महोत्सव बना विश्व का सबसे बड़ा राखी महोत्सव : विश्वास कैलाश सारंग

भोपाल (नप्र)। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का वह पावन पर्व है, जिसमें एक धागा रिश्ते की परिभाषा को रक्त संबंधों से आगे ले जाकर विश्वास, कर्तव्य, सुरक्षा, सम्मान और आत्मीयता से जोड़ देता है। कलाई पर बंधने वाला रक्षासूत्र आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन उसके भीतर निहित भावनाएं अनंत होती हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी रक्षाबंधन आज भारतीय जनमानस में उतनी ही श्रद्धा और आत्मीयता के साथ जीवंत है।

सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां पर्व केवल उत्सव नहीं होते, वे जीवन दर्शन के वाहक होते हैं। प्रत्येक पर्व मनुष्य को स्वयं से, परिवार को समाज से और समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। रक्षाबंधन भी इसी महान परंपरा का पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास और जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं।

इसी सांस्कृतिक और सामाजिक भावना को केंद्र में रखकर 18 वर्ष पूर्व नरेला में रक्षाबंधन महोत्सव प्रारंभ किया था। तब मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि हर बहन को यह विश्वास दिलाना कि मैं उनका भाई हूं, उनका रक्षक हूं और उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए सदैव समर्पित रहूंगा।

आज वही भावना एक सामाजिक उत्सव का रूप ले चुकी है। हर वर्ष लाखों बहनें मुझे रक्षासूत्र बांधकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पिछले वर्ष 1 लाख 84 हजार 632 बहनों ने रक्षासूत्र बांधकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह संख्या केवल एक रिकॉर्ड नहीं है। यह लाखों बहनों के विश्वास, स्नेह और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। इसी अपार स्नेह ने नरेला रक्षाबंधन महोत्सव को

विश्व के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव के रूप में पहचान दिलाई है लेकिन किसी भी आयोजन की वास्तविक सफलता उसके आकार से नहीं बल्कि समाज पर उसके प्रभाव से तय होती है। नरेला के इस महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अब यह पर्व केवल नरेला परिवार तक सीमित नहीं रहा बल्कि भोपाल की अन्य विधानसभाओं की बहनें भी बड़ी संख्या में मुझे रक्षासूत्र बांधती हैं।

सीधी-सिंगरौली रोड हुआ बंद

खाखन नाले में उफान के बाद एनएच-39 के ऊपर बह रहा है पानी

सिंगरौली (नप्र)। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र रीवा सतना सिंगरौली सीधी में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी नाले उफान में आने के कारण आने वजह से सीधी सिंगरौली मार्ग एनएच-39 में देवसर समीप बने खाखन नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ से बैरकेडिंग कर दी गई है।

रोड कर दिया गया बंद- आने जाने वाले लोगों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। सड़क के किनारे दोनों तरफ से भारी वाहन लाइन से खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से आने जाने वाले लोगों को दूसरे रास्ते से डायवर्ट कर पहुंच मार्ग तक जाने के लिए अन्य रास्तों के उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।

दो लोगों के बहने की सूचना- सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी मिली थी कि दो बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह जाने की सूचना है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की सूचना की पुष्टि नहीं की है। मौके पर एसडीएम एसडीओपी थाना प्रभारी समेत अन्य विभाग के अधिकारी यहां पर उपस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कर्मचारियों की इसकी सूचना दी गई है।

सीधी से सिंगरौली का संपर्क टूटा- हालांकि खाखन नदी में बने नाले पानी बहने के कारण सीधी सिंगरौली मुख्य मार्ग का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक रास्ता उपयोग करने की सलाह दी है।

गौरतलब है कि विंध्य इलाके में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। इसकी वजह से सतना, रीवा और चित्रकूट में स्थिति बिगड़ी थी। अब प्रशासन ने बाढ़ वाले मार्गों पर निकलने से पहले एहतियात बरतने की अपील की है।

कही-सुनी

कौन होगा छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष ?

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

चर्चा है कि अस्वस्थ चल रहे छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव की जगह किसी नए नेता को कमान सौंपने का फैसला बीजेपी हाईकमान ने कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को कुछ घंटों के लिए नई दिल्ली गए थे। बताते हैं उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाक़ात हुई। खबरों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए करीब दो घंटे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव पिछले दिनों एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कहते हैं किरण सिंह देव को स्वस्थ होने में अभी कुछ महीने लगेंगे, ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जरुरी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का नाम चर्चा में हैं। तोखन साहू ओबीसी हैं और साहू समाज से हैं। राज्य में साहू समाज का करीब 12 फीसदी वोट है। तोखन साहू को छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी दिए जाने की स्थिति में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। संतोष पांडे दूसरी बार के सांसद हैं। दुर्ग के सांसद विजय बघेल भी दूसरी बार के सांसद हैं और ओबीसी भी हैं, पर राज्य सत्ता से विजय बघेल का संबंध मधुर नहीं है। आठ बार के विधायक और संयुक्त मध्यप्रदेश में सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल से लेकर डॉ रमनसिंह और विष्णुदेव साय के कैबिनेट में रहे बृजमोहन अग्रवाल भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने की दौड़ में हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्दी ही फेरबदल होने वाला है।

- **मुराद पूरी नहीं हुई भाजपा नेता की-** कहते हैं छत्तीसगढ़ के एक भाजपा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में बड़े पोजीशन में जाने के इच्छुक थे। इसके लिए भाजपा नेता ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली में एक-दो कार्यक्रम भी करवाए और अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन टीम बनी तो उन्हें निराशा हाथ लगी। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ से अपनी टीम में रूपकुमारी चौधरी और दीपक म्हस्के को ले लिया। कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने के इच्छुक भाजपा नेता को नितिन नवीन की सिफारिश पर सरकार में एक पद भी मिला हुआ है। इस कारण नेताजी को नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर उनकी टीम में जगह मिलने का मुगालता हो गया था। पर जब दिन फिरते हैं तो हर चीज के नतीजे उलटे आने लगते हैं। यही नेताजी के साथ हो गया। चर्चा है कि नेताजी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में प्रचार को लेकर कुछ लोगों के निशाने पर आ गए।
- **बड़े आईपीएस पीएचक्यू से बाहर-** हाल के फेरबदल में डीजीपी की दौड़ में शामिल सभी बड़े आईपीएस अफसर पुलिस मुख्यालय से बाहर कर दिए गए। बिना प्रभार के चल रहे 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को डीजी प्रशिक्षण बनाकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भेज दिया गया। कहते हैं जीपी सिंह की इच्छा ईओडब्ल्यू में डीजी बनने की थी। जीपी सिंह पहले ईओडब्ल्यू के प्रभारी रह चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रशासन देख रहे आईपीएस एस आर पी कल्लूरी को पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन का एमडी बना दिया गया। एस आर पी कल्लूरी भी 1994 बैच के आईपीएस हैं। 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता डीजी जेल के तौर पर पहले से ही पुलिस मुख्यालय से बाहर हैं। कई वर्षों से पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रभारी रहे पवन देव को होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। अभी तक होमगार्ड के डीजी का प्रभार अतिरिक्त रूप से डीजी अरुणदेव गौतम संभाल रहे थे। पवन देव 1992 बैच के आईपीएस हैं। पुलिस मुख्यालय के फेरबदल में आईपीएस विवेकानंद,अमित कुमार और प्रदीप गुप्ता का कद बढ़ाया गया।
- **ओएसडी के जिम्मे विभाग-** कहते हैं विष्णुदेव साय के एक मंत्री ने अपना एक विभाग एक ओएसडी के हवाले कर दिया है। मंत्री जी के पास तीन-चार विभाग हैं। चर्चा है कि ओएसडी साहब अफसरों की पोस्टिंग से लेकर नीतिगत निर्णय तक लेते हैं। मंत्री जी पहले भी अपना एक विभाग एक ओएसडी के भरोसे छोड़ दिया था। हल्ला होने के बाद मंत्री से वह विभाग छिन गया। विभाग जाने के कुछ दिनों बाद ओएसडी भी रवाना हो गए। अब नए ओएसडी साहब आए हैं। उनके जिम्मे एक बड़ा विभाग है। मंत्री जी अनुभवी और पुराने खिलाड़ी हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता को काफी नजदीक से समझने के बाद भी उनका एक विभाग ओएसडी के हवाले क्यों है। मंत्री जी को भाजपा की राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा भी माना जा रहा है।
- **अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले ही अनुशासनहीन-** आमतौर पर पुलिस लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाती है और नियम-कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देती है, लेकिन पुलिस स्वयं ही अनुशासनहीन हो जाय और नियम-कानून को धता बता दे, तो क्या कहा जाय। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस की कहानी है। कोरबा जिले के कटघोरा थाने की पुलिस एक ठगी के मामले की जाँच के लिए दूसरे प्रांत में ट्रेन की जगह प्लेन से चले गए। वह भी सरकारी खर्चे से नहीं, एक पीड़ित ने खर्च उठाया। जाँच के लिए एक-दो लोग नहीं, बल्कि आठ लोग गए। थानेदार से लेकर सिपाही तक सभी ने हवाई सफर का आनंद उठा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद बिलासपुर के आईजी रामगोपाल गर्ग ने सभी को निलंबित कर दिया है। पर पुलिस कर्मियों के कृत्य ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले अंबिकापुर के कुछ पुलिस वालों पर जाँच और मामला रफा-दफा करने के लिए हवाला से पैसा लेने का आरोप लगा। आखिर छत्तीसगढ़ की पुलिस किधर जा रही है।
- **आईएएस के भाई की तूती-** कहते हैं कि एक आईएएस अफसर के भाई की एक निगम में इन दिनों तूती बोल रही है। अफसर इस निगम के कर्ताधर्ता हैं। बताते हैं अफसर अपने भाई के मार्फ़त ही काम करते हैं। भाई ठेकेदारों से संपर्क करता है और उनकी पसंद का काम दिलाता है। वैसे एक जमाने में इस निगम में काफी काम थे और यह चर्चा में भी था। पर निगम में इन दिनों पहले जैसी रौनक बची नहीं। ठेकेदार रूचि नहीं ले रहे हैं। अब भाई के मार्फ़त कुछ डील हो जाते हैं।